गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 232
दि. 23.12.2025,
मंगलवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

रेल किराया बढ़ोतरी से गरमाई सियासत, मोदी सरकार पर जनता से लूट का आरोप, खरगे ने रेलवे की कार्यप्रणाली पर उठाए गंभीर सवाल

(जीएनएस)। नई दिल्ली। रेल मंत्रालय द्वारा ट्रेन टिकट के दाम बढ़ाने के फैसले के बाद देश की राजनीति में एक बार फिर रेलवे को लेकर तीखी बहस छिड़ गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इस बढ़ोतरी को आम जनता पर सीधा हमला बताते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता से पैसे वसूलने का कोई मौका नहीं छोड़ रही और बजट से ठीक पहले रेल किराया बढ़ाकर मध्यम वर्ग और गरीब यात्रियों पर अतिरिक्त बोझ डाला गया है।

मल्लिकार्जुन खरगे ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक विस्तृत पोस्ट के जरिए सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एक साल के भीतर दूसरी बार रेल किराया बढ़ाया जाना इस बात का प्रमाण है कि सरकार की प्राथमिकता आम लोगों की सुविधा नहीं, बल्कि राजस्व बढ़ाना है। खरगे ने यह भी कहा कि अलग रेलवे बजट को खत्म करने के बाद रेलवे की जवाबदेही लगभग समाप्त हो गई है और अब संसद में रेलवे से जुड़े मुद्दों पर गंभीर बहस नहीं हो पा रही है। उनके अनुसार, मोदी सरकार के कार्यकाल में रेलवे की स्थिति लगातार खराब हुई है, लेकिन सरकार केवल प्रचार में व्यस्त है।

रेल मंत्रालय द्वारा रविवार को घोषित नए किराया ढांचे के मुताबिक साधारण श्रेणी में 215 किलोमीटर से अधिक की यात्रा पर प्रति किलोमीटर 1 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, जबकि

मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की नॉन-एसी श्रेणी और सभी ट्रेनों की एसी क्लास में प्रति किलोमीटर 2 पैसे का इजाफा किया गया है। सरकार भले ही इसे मामूली बढ़ोतरी बता रही हो, लेकिन विपक्ष का कहना है कि रोजमर्रा की यात्रा करने वाले करोड़ों यात्रियों के लिए यह फैसला जेब पर भारी पड़ने वाला है। इस घोषणा के बाद से ही राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं।

खरगे ने किराया बढ़ोतरी के साथ-साथ रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी गंभीर चिंता जताई। उन्होंने एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया कि वर्ष 2014 से 2023 के बीच रेलवे हादसों में 2.18 लाख लोगों की मौत हुई है। उनके मुताबिक यह आंकड़े इस बात का संकेत हैं कि रेलवे में सुरक्षा को लेकर सरकार पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने रेल सुरक्षा प्रणाली 'कवच' को लेकर भी सरकार को घेरा और कहा कि पिछले पांच वर्षों से इसके बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यह प्रणाली अब तक 3 प्रतिशत से भी कम रेल मार्गों और 1 प्रतिशत से कम इंजनों में ही लागू हो पाई है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने रेलवे में मानव संसाधन की स्थिति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि रेलवे में इस समय करीब 3.16 लाख पद खाली पड़े हैं, जिससे काम का बोझ बढ़ रहा है और सुरक्षा पर भी असर पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि युवाओं को स्थायी नौकरी देने के बजाय ठेके पर भर्तियां बढ़ाई जा रही हैं, जिससे न तो कर्मचारियों को सुरक्षा मिल रही है और न ही सेवा की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास के लिए आवंटित फंड का पूरा उपयोग नहीं किया गया। उनके अनुसार 2023-24 में सिर्फ 42 प्रतिशत और 2024-25 में दिसंबर तक महज 68 प्रतिशत राशि ही खर्च हो पाई।

खरगे ने लोको पायलटों को पर्याप्त आराम न मिलने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह सीधे तौर पर यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ा विषय है। उन्होंने अमृत भारत योजना के तहत स्टेशनों के विकास में हो रही देरी पर भी सवाल खड़े किए। उनका दावा है कि 453 स्टेशनों के उन्नयन के लक्ष्य के मुकाबले अब तक सिर्फ एक स्टेशन पर ही काम पूरा हो सका है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रेलवे को 2,604 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, जबकि वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली रियायतें खत्म कर उनसे 8,913 करोड़ रुपये वसूले गए हैं। वंदे भारत ट्रेनों को लेकर भी खरगे ने सरकार के दावों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जहां सरकार इन ट्रेनों की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटे बताती है, वहीं वास्तविकता में इनकी औसत गति केवल 76 किलोमीटर प्रति घंटे ही है। कुल मिलाकर किराया बढ़ोतरी के फैसले ने न सिर्फ यात्रियों में नाराजगी पैदा की है, बल्कि विपक्ष को सरकार पर हमलावर होने का एक और मुद्दा दे दिया है। आने वाले दिनों में यह विवाद संसद से लेकर सड़कों तक और तेज होने के संकेत दे रहा है।

गोवा अग्निकांड में बड़ा अपडेट, लूथरा बंधुओं की पुलिस हिरासत पांच दिन बढ़ी, विदेशी फरार आरोपियों पर शिकंजा कसने की तैयारी

(जीएनएस)। पणजी। गोवा के चर्चित अग्निकांड मामले में जांच तेज होती नजर आ रही है। राजधानी पणजी की एक अदालत ने सोमवार को बर्च बाय रोमियो लेन नाइटक्लब अग्निकांड के मुख्य आरोपियों सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा की पुलिस हिरासत पांच दिन के लिए बढ़ा दी है। यह वही नाइटक्लब है, जहां छह दिसंबर को भीषण आग लगने से 25 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया था और सुरक्षा मानकों की गंभीर अनदेखी को लेकर प्रशासन और नाइटलाइफ उद्योग पर सवाल खड़े कर दिए थे।

सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा इस नाइटक्लब के मालिक हैं और घटना के तुरंत बाद दोनों भाई देश छोड़कर थाईलैंड फरार हो गए थे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दबाव और कानूनी प्रक्रिया के बाद 17 दिसंबर को दोनों को थाईलैंड से भारत वापस भेजा गया, जिसके बाद गोवा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मामले की सुनवाई के दौरान पीड़ितों के परिवारों की ओर से पेश अधिवक्ता विष्णु जोशी ने अदालत को बताया कि जांच अभी निर्णायक मोड़ पर है और कई अहम पहलुओं

की पड़ताल के लिए पुलिस को आरोपियों से और पूछताछ की जरूरत है। अदालत ने दलीलों को स्वीकार करते हुए दोनों लूथरा भाइयों की पुलिस हिरासत पांच दिन के लिए बढ़ाने का आदेश दिया।

अदालत ने इस मामले में एक अन्य महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए क्लब के मालिकों में शामिल अजय गुप्ता को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने अजय गुप्ता की हिरासत बढ़ाने का अनुरोध नहीं किया, जिसके चलते अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। इससे साफ है कि जांच एजेंसियां अब आरोपियों की भूमिका को अलग-अलग स्तर पर परख रही हैं और जिनसे पूछताछ पूरी हो चुकी है, उनके खिलाफ आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

इस भीषण अग्निकांड को लेकर अंजुना पुलिस ने लूथरा बंधुओं के खिलाफ गैर इरादतन हत्या सहित कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि नाइटक्लब में सुरक्षा के जरूरी इंतजाम नहीं थे और नियमों की घोर अनदेखी के चलते इतनी बड़ी त्रासदी हुई। अब तक इस मामले में आठ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और जांच का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है।

जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि इस मामले से जुड़ा एक अहम आरोपी ब्रिटिश नागरिक सुरिंदर कुमार खोसला घटना के बाद से ही फरार है और वह ब्रिटेन भाग चुका है। गोवा पुलिस ने उसके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, ताकि उसकी लोकेशन का पता लगाया जा सके और उसे भारत लाने की कानूनी कार्रवाई तेज की जा सके। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि विदेश भागे आरोपियों के खिलाफ इंटरपोल के माध्यम से कार्रवाई की जा रही है और किसी को भी कानून से बचने नहीं दिया जाएगा।

गोवा अग्निकांड में लगातार सामने आ रहे नए खुलासों ने यह साफ कर दिया है कि मामला केवल एक हादसा नहीं, बल्कि गंभीर लापरवाही और नियमों की अनदेखी का नतीजा है। पीड़ित परिवार न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं और प्रशासन पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। आने वाले दिनों में इस मामले में और गिरफ्तारियां और बड़े खुलासे होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

पूर्व आईजी अमर सिंह चहल ने खुद को मारी गोली गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, पंजाब में हड़कंप

(जीएनएस)। पटियाला। पंजाब के पूर्व वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और राज्य के पुलिस महानिरीक्षक रह चुके अमर सिंह चहल द्वारा खुद को गोली मारने की घटना से प्रदेश में सनसनी फैल गई है। यह घटना सोमवार को पटियाला स्थित उनके आवास पर हुई, जहां उन्होंने कथित तौर पर आत्महत्या करने की कोशिश की। गोली चलने की आवाज सुनते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई और पुलिस को तत्काल सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने चहल को गंभीर हालत में पाया और उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है।

पटियाला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वरुण शर्मा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस को गोली चलने की सूचना मिली थी, जिसके बाद कई टीमें तुरंत पूर्व आईजी के आवास पर भेजी गईं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार चहल को गंभीर चोटें आई हैं और डॉक्टरों की एक विशेष टीम उनका इलाज कर रही है। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि घटना किन परिस्थितियों में हुई और इसके पीछे के वास्तविक कारण क्या हैं।

पुलिस जांच के दौरान घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है, जिसने इस मामले को और गंभीर बना दिया है। पुलिस के मुताबिक नोट में अमर सिंह चहल ने खुद को एक वित्तीय धोखाधड़ी का शिकार बताया है। हालांकि नोट में किन लोगों या परिस्थितियों का जिक्र किया गया है, इस बारे में पुलिस ने फिलहाल कोई विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। अधिकारियों का कहना है कि नोट को जांच का अहम हिस्सा माना गया है और इससे जुड़े हर पहलू की बारीकी से पड़ताल की जा रही है।

यह घटना इसलिए भी ज्यादा चर्चा में है क्योंकि अमर सिंह चहल का नाम पहले से ही चर्चित कोटकपूरा और बेहबल कलां गोलीबारी मामलों से जुड़ा हुआ है। वर्ष 2015 में फरीदकोट जिले के बेहबल कलां और कोटकपूरा में हुई गोलीबारी की घटनाओं ने पूरे पंजाब को झकझोर दिया था। इन मामलों में रिटायर्ड पुलिस महानिरीक्षक अमर सिंह चहल को भी आरोपियों में शामिल किया गया था। फरवरी 2023 में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एल के यादव के नेतृत्व वाली विशेष जांच टीम ने फरीदकोट की एक अदालत में कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें चहल का नाम भी शामिल था।

पूर्व आईजी की ओर से आत्महत्या की कोशिश की खबर सामने आने के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में भी हलचल तेज हो गई है। कई लोग इस घटना को उनके खिलाफ चल रहे मामलों और कथित आर्थिक तनाव से जोड़कर देख रहे हैं, हालांकि पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने से पहले किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। पुलिस यह भी स्पष्ट कर रही है कि चहल का इलाज प्राथमिकता है और उनके बयान दर्ज करने की स्थिति बनने के बाद ही आगे की कानूनी प्रक्रिया पर फैसला लिया जाएगा। फिलहाल पूरा मामला जांच के दायरे में है और पंजाब पुलिस हर पहलू से तथ्यों को खंगालने में जुटी है। एक ओर जहां एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की इस हालत ने सभी को झकझोर दिया है, वहीं दूसरी ओर इससे जुड़े पुराने मामलों और सुसाइड नोट में किए गए खुलासों ने इस प्रकरण को और भी संवेदनशील बना दिया है। आने वाले समय में जांच के साथ-साथ चहल की स्वास्थ्य स्थिति पर पूरे राज्य की नजर बनी हुई है।

छात्र आंदोलन से उठी आवाज़, अफसरशाही की संवेदनशीलता पर बहस, टीना डाबी विवाद ने पकड़ा सियासी तूल

(जीएनएस)। मुंबई/बाड़मेर। राजस्थान कैडर की आईएएस अधिकारी टीना डाबी को लेकर उपजा ताजा विवाद अब केवल एक प्रशासनिक कार्रवाई तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि उसने छात्र अधिकारों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अफसरशाही की जवाबदेही जैसे बड़े सवालों को जन्म दे दिया है। कॉलेज फीस बढ़ोतरी के खिलाफ हो रहे छात्र आंदोलन के दौरान कुछ छात्र नेताओं पर की गई पुलिस कार्रवाई ने राजनीतिक रंग ले लिया है और इस पूरे घटनाक्रम पर शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने तीखी प्रतिक्रिया देकर बहस को और तेज कर दिया है।

मामला राजस्थान के बाड़मेर जिले के मुल्तानमल भीखचंद छाजेड़ महिला कॉलेज से जुड़ा है, जहां फीस में बढ़ोतरी के फैसले के खिलाफ छात्र-छात्राएं लंबे समय से नाराज़गी जता रहे थे। इसी नाराज़गी के बीच छात्रों ने प्रदर्शन किया, जिसमें एबीवीपी से जुड़े दो छात्र नेता भी शामिल थे। प्रदर्शन के दौरान हालात तनावपूर्ण होने की बात कहकर पुलिस ने दोनों छात्र नेताओं को हिरासत में ले लिया। छात्रों का आरोप है कि एक छात्र नेता द्वारा जिला कलेक्टर टीना डाबी को 'रील स्टार' कहे जाने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की, जिसे उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा प्रहार बताया।

छात्र नेताओं की हिरासत की खबर फैलते ही कॉलेज की कई छात्राएं कोतवाली थाने पहुंच गईं और वहां धरने पर बैठ गईं। छात्राओं का कहना था कि फीस बढ़ोतरी के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध करना उनका अधिकार है और प्रशासन को बातचीत के जरिए समाधान निकालना चाहिए था, न कि पुलिस कार्रवाई के माध्यम से डराने की कोशिश करनी चाहिए थी। छात्राओं ने इसे प्रशासनिक अहंकार का उदाहरण बताते हुए तुरंत रिहाई की मांग की।

इस पूरे घटनाक्रम पर सियासी प्रतिक्रिया तब और तेज हो गई जब शिवसेना (यूबीटी) की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया पर कड़ा बयान दिया। उन्होंने लिखा कि यह भारत में अफसरशाही की असहिष्णुता का एक और उदाहरण है, जहां सत्ता के नशे में बैठे लोग जवाबदेही से बचने की कोशिश करते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने सवाल उठाया कि जब छात्र अपनी फीस और भविष्य से जुड़े मुद्दों पर आवाज उठाते हैं तो उन्हें दबाने के लिए प्रशासनिक ताकत का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। उनका यह बयान देखते ही देखते राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया।

वहीं दूसरी ओर, जिला कलेक्टर टीना डाबी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हिरासत की कार्रवाई किसी व्यक्तिगत टिप्पणी या आलोचना के कारण नहीं, बल्कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से की गई थी। टीना डाबी के अनुसार प्रदर्शन के दौरान अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ और हालात बिगड़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी छात्र नेता पर कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है और सभी को बाद में रिहा कर दिया गया।

टीना डाबी ने यह भी दोहराया कि प्रशासन छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से लेता है, लेकिन विरोध प्रदर्शन के नाम पर अव्यवस्था फैलाने या अधिकारियों से अभद्रता को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि कॉलेज फीस से जुड़े मुद्दों पर नियमानुसार बातचीत और समाधान का रास्ता खुला है।

गौरतलब है कि टीना डाबी 2016 बैच की आईएएस अधिकारी हैं और उन्होंने महज 22 वर्ष की उम्र में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में प्रथम रैंक हासिल कर देशभर में पहचान बनाई थी। अपनी लोकप्रियता और सोशल मीडिया मौजूदगी के कारण वह अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। यही वजह है कि इस मामले ने भी तेजी से राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींच लिया।

कक्षा में उपग्रह स्थापित करने में विफल रहा जापान का H3 रॉकेट, स्वतंत्र नेविगेशन सिस्टम के सपने को झटका

(जीएनएस)। तनेगाशिमा। जापान के अंतरिक्ष कार्यक्रम को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। देश का नया फ्लैगशिप लॉन्च वाहन H3 रॉकेट अपने मिशन में पूरी तरह सफल नहीं हो सका और मिचिबिकी-5 नेविगेशन उपग्रह को निर्धारित कक्षा में स्थापित करने में विफल रहा। यह घटना न केवल जापान के महत्वाकांक्षी स्पेस लॉन्च प्रोग्राम के लिए चिंता का विषय है, बल्कि अमेरिकी जीपीएस प्रणाली पर निर्भरता खत्म करने की उसकी दीर्घकालिक योजना पर भी सवाल खड़े करती है।

जापानी अंतरिक्ष अन्वेषण अभिकरण (जाक्सा) के अनुसार, H3 रॉकेट को सोमवार को दक्षिण-पश्चिमी जापान के तनेगाशिमा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। इस रॉकेट के जरिए मिचिबिकी-5 उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा गया, जो जापान के अपने उच्च-सटीकता वाले नेविगेशन सिस्टम को मजबूत करने का अहम हिस्सा था। लॉन्च के शुरुआती चरण सामान्य रहे, लेकिन मिशन के बाद के हिस्से में उपग्रह को तय ऑर्बिट में स्थापित करने की प्रक्रिया सफल नहीं हो सकी, जिससे पूरा मिशन अधूरा रह गया। यह H3 रॉकेट के लिए दूसरी बड़ी नाकामी मानी जा रही है। मार्च 2023 में इसकी पहली उड़ान के दौरान दूसरे चरण के इंजन के सक्रिय न हो पाने के कारण मिशन विफल हो गया था। इसके बाद हालांकि H3 ने छह सफल उड़ानें भरी थीं, जिससे यह उम्मीद जगी थी कि जापान अपने नए लॉन्च सिस्टम को स्थिर और भरोसेमंद बना चुका है। ताजा असफलता ने एक बार फिर इस रॉकेट की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

H3 रॉकेट को जापान के पुराने और बेहद सफल H-2A रॉकेट की जगह लेने के लिए विकसित किया गया था। H-2A का सफलता रिकॉर्ड काफी मजबूत रहा है और उसी के भरोसे जापान ने दशकों तक अपने महत्वपूर्ण उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे। H3 को कम लागत, अधिक लचीलापन और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया था, ताकि जापान वैश्विक अंतरिक्ष प्रक्षेपण बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धा बढ़ा सके। इस मिशन की विफलता का असर केवल तकनीकी स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका रणनीतिक महत्व भी है। मिचिबिकी-5 उपग्रह, क्वासी-जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम यानी क्यूजेडएसएस का हिस्सा था। यह सिस्टम जापान की अपनी सटीक लोकेशन और नेविगेशन क्षमता को मजबूत करने के लिए बनाया गया है, ताकि स्मार्टफोन, समुद्री जहाजों, ड्रोन और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में अमेरिकी जीपीएस पर निर्भरता कम की जा सके। फिलहाल जापान के पास इस नेटवर्क में पांच उपग्रह हैं, जिसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। मिचिबिकी-5 इसके नेटवर्क का छठा उपग्रह बनने वाला था।

संपादकीय

काग़ज़, स्याही और स्मृतियाँ: चालीस साल पुराने समय में लौटने का एहसास

पिछले दिनों एक ऐसे लेखक से मुलाक़ात हुई, जिन्हें दुनिया भले न जानती हो, लेकिन जिनकी लिखी पंक्तियाँ कई नामचीन हस्तियों के नाम से छपीं और सराही गईं। वह एक प्रेत-लेखक थे, यानी घोस्ट राइटर। लिखना उनका पेशा रहा, लेकिन नाम हमेशा किसी और का। उम्र अस्सी-पचासी के आसपास, अनुभव से भरी आँखें और शब्दों से लबालब ज़िंदगी। उनका फ्लैट किसी छोटे से पुस्तकालय जैसा था—हर तरफ़ किताबें, पत्रिकाएँ, अख़बार, जैसे समय को सहेज कर रखा गया हो। बातचीत के दौरान उन्होंने जिन- जिन लोगों के लिए लिखा, उनके नाम बताए, मगर उससे ज़्यादा दिलचस्प था वह दुनिया, जो उन काग़ज़ों में छिपी थी।

उसी ढेर में से मैंने एक पुरानी पत्रिका उठा ली। लगभग चालीस साल पुरानी। उसके पन्ने पलटते ही एक अलग ही दौर सामने खुलने लगा। क्रिकेट और फुटबॉल की खबरों से भरे पन्ने, मैच रिपोर्ट्स, खिलाड़ियों के इंटरव्यू—सब कुछ आज की चकाचौंध भरी डिजिटल दुनिया से बिल्कुल अलग। शब्दों में ठहराव था, तस्वीरों में सादगी और खबरों में एक किस्म की मासूमियत।

सबसे ज़्यादा आनंद मुझे उन पुराने विज्ञापनों को देखने में आया। फ्रंट कवर के अंदर की साइड पर थम्स-अप का विज्ञापन दिखा, जिसमें सुनील गावस्कर और इमरान ख़ान एक साथ बैठे बोतल से थम्स-अप का मज़ा ले रहे थे। एक तस्वीर, जिसमें दो देशों के खिलाड़ी, मुस्कान और सहजता के साथ। तस्वीर देखते हुए मन अनायास ही तुलना करने लगा कि इन चालीस सालों में दोनों मुल्कों के रिश्ते कहां से कहां पहुंच गए। तब खेल और खिलाड़ी जोड़ने का काम करते थे, आज वही चीज़ें अक्सर बहस और विवाद का कारण बन जाती हैं।

आगे पन्ने पलटे तो अवंती गैरेली मोपेड का विज्ञापन दिखा। फिर लूना। कितना अर्सा हो गया था लूना को देखे हुए। आज के भारी-भरकम बाइक्स और स्कूटरों के दौर में वह हल्की-फुल्की मोपेड जैसे किसी और ज़माने की चीज़ लगती है। लेकिन चालीस साल पहले लोग भी तो उतने भारी-भरकम नहीं थे। दुबले-पतले, स्लिम-ट्रिम लोग, जिन्हें लूना और अवंती आराम से ढो लेती थीं। एक आदमी आगे, पीछे उसकी पत्नी—और ज़िंदगी अपनी रफ्तार से चलती रहती थी।

मैं जब-जब मैगज़ीन के पन्नों की तस्वीरें मोबाइल में कैद करता, वह प्रेत-लेखक मुस्कुराते हुए पूछते, "क्या करोगे इनका?" मैंने कहा, "इनसे एक कहानी बुनूंगा।" शायद उन्हें अच्छा लगा कि उनकी दुनिया के ये टुकड़े किसी और की यादों का हिस्सा बनने जा रहे हैं। बाटा के पावर शूज़ का विज्ञापन दिखा, फिर कावासाकी बजाज मोटरसाइकिल। उस दौर की मोटरसाइकिलों का ज़िक्र आते ही अपने आप एक पूरा समय आंखों के सामने घूम गया।

तब हमें मोटरसाइकिल के नाम पर बस तीन ही गाड़ियां पता थीं। एक राजदूत, जिसे कहा जाता था कि दूध वाले खरीदते हैं—मज़बूत, भरोसेमंद और भारी। दूसरी फैशनेबल येज़्दी, जो युवाओं की शान मानी जाती थी। और तीसरी बुलेट, जिसे रुआबदार लोग रखते थे, जिनकी आवाज़ दूर से ही पहचान में आ जाती थी। जनवरी 1986 की बात है, जब मुझे अपने बड़े भाई से एक येज़्दी मोटरसाइकिल मिली थी। आज भी उसकी आवाज़, उसकी गंध और उसे चलाने का एहसास यादों में ताज़ा है।

किसी पुरानी मैगज़ीन को हाथ में लेकर उसके कंटेंट को पढ़ना सिर्फ़ पढ़ना नहीं होता, वह जैसे गुज़रे हुए समय को दोबारा जी लेने जैसा अनुभव होता है। हर विज्ञापन, हर तस्वीर, हर लाइन किसी न किसी स्मृति से जुड़ जाती है। वह दौर, जब चीज़ें कम थीं लेकिन यादें ज़्यादा बनती थीं।

इसी सिलसिले में एक और याद ताज़ा हो गई। 1990 में दिल्ली में हम लोग श्रीमती जी के मौसा जी के घर गए थे। पढ़ने-लिखने के शौकीन, कपूर साहब। उनके कमरे में कदम रखते ही लगा जैसे किताबों का समुद्र हो। चारों तरफ़ किताबें ही किताबें। वह इंग्लिश के टीचर थे, इसलिए ज़्यादातर किताबें भी अंग्रेज़ी की थीं। मैं जब उनके साथ बैठकर किताबों और लेखकों की बातें करता, तो अपनी-अपनी यादें साझा करते हुए हम खूब हंसते। वह हंसी, वह बातचीत, वह माहौल—सब कुछ आज भी मन में दर्ज है।

चालीस साल पुराने काग़ज़ों की वह महक, उन पर छपी तस्वीरें और शब्द, और उनसे जुड़ी यादें—यह सब मिलकर यह एहसास दिला गया कि समय चाहे जितना बदल जाए, कुछ दौर ऐसे होते हैं जो दिल में हमेशा ज़िंदा रहते हैं। शायद इसलिए पुरानी पत्रिकाएँ, किताबें और अख़बार सिर्फ़ काग़ज़ नहीं होते, वे हमारे अपने इतिहास के पन्ने होते हैं, जिन्हें पलटते ही हम खुद से फिर मिल लेते हैं।

'जी-राम-जी' बनाम मनरेगा की तार्किकता का प्रश्न

> "सत्तापक्ष के पास हमेशा से संख्या बल रहा है, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं था कि 'जी-राम-जी' मनरेगा की जगह ले लेगा, भले ही कांग्रेस ने संसद के बाहर लगी गांधी की प्रतिमा के सामने कितने भी विरोध प्रदर्शन किए हों।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय संसद की बजाय इथियोपियाई संसद को चुना, विपक्ष के नेता राहुल गांधी म्यूनिख में एक फैंसी बाइक चलाते हुए देखे गए, जबकि उन्हें लोकसभा में बने रहकर राष्ट्र को दरपेश अनेकानेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस करनी चाहिए थी, वहीं विदेश मंत्री एस. जयशंकर राज्यसभा की बजाय इस्राइल में थे। गत सप्ताह, शीतकालीन सत्र में सदन से तीन प्रमुख नेताओं के नदारद रहने पर, आप हैरान होंगे : क्या यह संसद की प्रासंगिकता का प्रश्न नहीं है?

यह एक अल्पकालीन सत्र था, हालिया इतिहास के सबसे छोटे सत्रों में से एक। लेकिन इसमें लाए गए महत्वपूर्ण कानूनों की कोई कमी नहीं थी, इनमें सबसे अहम है, प्रति परिवार, प्रति वर्ष 125 दिनों के काम के लिए मजदूरी से संबंधित 'जी-राम-जी कानून', जिसको सत्र समाप्त होने से एक दिन पहले पारित किया गया। चूंकि सत्तापक्ष के पास हमेशा से संख्या बल रहा है, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं था कि 'जी-राम-जी' मनरेगा की जगह ले लेगा, भले ही कांग्रेस ने संसद के बाहर लगी गांधी की प्रतिमा के सामने कितने भी विरोध प्रदर्शन किए हों।

विपक्ष ने भी यह पूछा कि कानून का नाम क्यों बदला जा रहा है। क्यों महात्मा गांधी के संक्षिप्त नाम के पहले दो अक्षर एमजी को राम से बदला जा रहा है, जबकि सरकार वर्णमाला के किसी भी अन्य शब्द को चुन सकती थी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने कानून को पेश करने के काम की अगुवाई, अन्यथा बढ़िया ढंग से की, उनके पास कोई उचित जवाब नहीं था। संसद में गांधी के आदर्श 'राम राज्य', स्वयं भगवान राम के प्रति उनकी निष्ठा के बारे में भाषणों की गूंज सुनाई दी- लेकिन इस बात का कोई असल कारण नहीं बताया गया कि मनरेगा में बदलाव क्यों किया गया, न तो बातों में और न ही कार्यरूप में।

दिलचस्प बात यह है कि 'जी-राम-जी' का एक पिछला स्वरूप भी था, जिसका जीवनकाल 24 घंटे का था। इसे 'पूज्य बापू ग्रामीण रोज़गार योजना' का नाम दिया गया था, जो कि अंग्रेजी में लिखे मूल नामकरण, 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम' का नज़दीकी हिंदी अनुवाद था। साफ है, भाजपा ने महात्मा गांधी, या पूज्य बापू को प्रतीकात्मक रूप से राम के नाम से बदलने का फैसला किया।

क्यों? वह हम नहीं जानते। कुछ लोग कहेंगे, आखिर नाम में क्या रखा है? कुछ लोगों का जवाब होगा, सब कुछ है। कि बापू की मृत्यु के लगभग 78 साल बाद, उनका नाम मिटाने की कोशिश है, जिसकी अहमियत को शायद, हम समझ भी न पाएं। गांधी मां-बेटी की जोड़ी ने नारे लगाए और सदन के बाहर मार्च किया, लेकिन कुछ हद तक यह सब आधा-अधूरा था। इस बीच, 'गांधी परिवार' के उत्तराधिकारी म्यूनिख में बीएमडब्ल्यू की साझेदारी में बन रही टीवीएस-450 सीसी मोटरसाइकल चलाते दिखे। हालांकि, पार्टी के कहे मुताबिक, वे वहां इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस के नेताओं से 'पार्टी की विचारधारा को विस्तार देने की रणनीतियों' पर चर्चा करने के वास्ते गए हैं। सवाल यह बना हुआ है कि किस देश में।

कुछ ही महीने पहले, राहुल ने बिहार चुनाव में कांटे की लड़ाई लड़ने की बजाय, 'पार्टी का विस्तार' करने के लिए दक्षिण अमेरिका जाने का फैसला किया था। ऐसा लगता है कि इस हफ्ते उनके पदचिन्ह जर्मनी में ही बने रहेंगे। अवश्य ही, जिस किस्म की दिखावेबाजी आजकल विपक्ष कर रहा है, वह आत्मघाती जैसा है। निश्चित तौर पर, अगर यह सब थोड़ा और समय तक चलता रहा, तो जल्द ही कांग्रेस पार्टी को पुनः एकजुट रखना न केवल असंभव होगा, बल्कि घातक भी होगा।

हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री संसद की गहमागहमी में इसलिए मौजूद नहीं थे क्योंकि ओमान के साथ मुक्त व्यापार समझौता हस्ताक्षरों के लिए तैयार था—यूके के बाद दूसरी संधि— लेकिन यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि इथियोपिया और जॉर्डन के दौरे इंतजार क्यों नहीं कर सकते थे। जॉर्डन नरेश हुसैन दो साल पहले ही भारत की यात्रा पर आए थे; वापसी दौरा किसी और वक्त भी रखा जा सकता था। जहां तक इथियोपिया की बात है, जिस संसद भवन में मोदी को बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था, भले ही वह चीनियों ने न बनाया हो, लेकिन पास के अदीस अबाबा में अफ्रीकी संघ का मुख्यालय उन्होंने ही बनाया है। दरअसल, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने अफ्रीका भर में 15 मुल्कों के संसद भवन बनाए हैं, लोकतंत्र के प्रति उनकी प्रतिबद्धता इतनी है।

बहरहाल, गत सप्ताह मोदी को इथियोपिया और ओमान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिले—ये उनके 28वें और 29वें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हैं। इस बीच, जब राहुल जर्मनी में छुट्टियां मना रहे थे तो एक कांग्रेस ने बिना सोचे-समझे सदन के बीचों-बीच आकर हंगामा किया। लेकिन यह तृणमूल कांग्रेस है, न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसने गुरुवार की रात को दिल्ली की तीखी ठंड में 'जी-राम-जी' पारित होने के विरोध में संसद की सीढ़ियों पर रात्रि के अधिकांश समय धरना दिया।

संसद की प्रासंगिकता का प्रश्न छोड़ भी दें, तो कांग्रेस की अप्रासंगिकता और उसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य से उसका अवसान होते जाना शायद इस हफ़्ते की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। यह हमारी आंखों के सामने घटित हो रहा है और इस अंतःस्राव को थामने वाला कोई नहीं है। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जो कि गांधी परिवार के अच्छे मित्र हैं, उन्होंने हाल ही में, संक्षेप में पुरसाहाल बता डाला था कि 'इंडिया' गठबंधन मरणासन्न है।

यहां तक कि लोकसभा में प्रियंका गांधी द्वारा हिंदी में की गई शानदार दखलअंदाज़ियां, जिसमें बीच-बीच में उनकी प्यारी मुस्कान भी शामिल थी, बीते कल की रोटी की तरह बेमजा रहीं। नितिन गडकरी से 'चंडीगढ़ से शिमला' सड़क की हालत पर चर्चा करने के लिए समय मांगना–जो कि शिमला के पास मशोबरा में बने उनके घर, जिसका निर्माण हिमाचल मंत्रिमंडल से मिली विशेष अनुमति से खरीदी गई जमीन पर हुआ है, उस तक पहुंचने की राह भी है—यह सब ठीक है, लेकिन ऐसी चीज़ें ठोस राजनीति का अवयव नहीं हैं।

अगर बीजेपी वास्तव में, देश को एकल-पार्टी चालित राष्ट्र में तब्दील कर रही है, जैसा कि प्रताप भानु मेहता जैसे बुद्धिजीवियों ने हाल ही में तर्क दिया है, तो सच्चाई यह है कि देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का हक पाए दल का कमज़ोर, किंतु विशेषाधिकार प्राप्त नेतृत्व बीजेपी को ऐसा करने दे रहा है। सरल बात है उसे कोई परवाह नहीं है।

इस बाबत आप कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, ज़्यादातर दबी हुई बड़बड़ाहट सुन सकते हैं। ओडिशा के पूर्व विधायक मोहम्मद मोकिम ने हिम्मत जुटाकर सोनिया गांधी से यह कहा कि उन्होंने तीन साल तक उनके बेटे से मिलने की कोशिश की, लेकिन मुलाकात का समय नहीं मिला। कहा जाता है कि गांधी परिवार की घेराबंदी किए बैठे लोगों की पकड़ इतनी मज़बूत है कि अगर आपकी पहुंच अलप्पुझा से सांसद और शक्तिशाली पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल तक नहीं है, तो आपका कोई महत्व नहीं है।

इसलिए, जब आप एक नए और साहसी साल में कदम रखेंगे, तो गांधी का यह कथन कि 'भारत अपने सूबों में भी बसता है' और भी ज़्यादा प्रासंगिक हो जाता है। असम, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव 2026 में गणतंत्र को परिभाषित करेंगे। घटकों को जोड़कर भी योग नहीं बन पाएगा क्योंकि बीजेपी अपने राजनीतिक विचारधारा और मनोस्थिति के चलते हरेक इंच की लड़ाई लड़ेगी। फिर भी, कांग्रेस के लिए टीएमसी, डीएमके और सीपीएम से कुछ बातें सीखना फायदेमंद होगा—लड़ा कैसा जाता है, और शायद, जीतना भी।

वर्ष 2026 एक निर्णायक साल होगा। क्या कांग्रेस वापसी करने में सक्षम होगी?

प्रेरणा

जब जीवन की समझ किताबों से नहीं, अनुभव से चलती है

एक साधारण-सी दिखने वाली कथा कई बार जीवन की जटिल सच्चाइयों को इतनी सहजता से खोल देती है कि बड़े-बड़े दर्शन भी फीके पड़ जाते हैं। तेली और दार्शनिक की यह कहानी भी कुछ ऐसी ही है। बाहर से देखने पर यह एक हल्का-फुल्का संवाद लगता है, जिसमें एक दार्शनिक अपने सवालों से तेली को उलझाने की कोशिश करता है और अंत में तेली की एक सीधी-सी बात पूरे तर्क-जाल को काट देती है। लेकिन अगर इस कथा को गहराई से देखें तो यह हमारे समाज, हमारी सोच और हमारे व्यवहार पर तीखा व्यंग्य भी है। तेली अपने कोल्हू के पास सो रहा है, बैल चुपचाप घूम रहा है, कोल्हू चल रहा है और काम हो रहा है। यह दृश्य अपने आप में एक व्यवस्था को दिखाता है। यहां कोई जटिल योजना नहीं है, कोई बड़े सिद्धांत नहीं हैं, बस अनुभव से बनी हुई एक सरल प्रणाली है। बैल की आंखों पर पट्टी इसलिए नहीं है कि उसे धोखा दिया जाए, बल्कि इसलिए है कि वह अपने स्वभाव के अनुसार बिना विचलित हुए चलता रहे। तेली को बैल पर भरोसा है, अपने अनुभव पर भरोसा है और उस व्यवस्था पर भरोसा है जिसे वह सालों से चला रहा है। दार्शनिक का प्रवेश इसी भरोसे को सवालों के कटघरे में खड़ा करता है। वह पूछता है, शक करता है, संभावनाएं गिनाता है। उसके लिए हर व्यवस्था तब तक अधूरी है, जब तक उसमें हर "अगर" और "मगर" का जवाब न हो। अगर बैल रुक गया तो? अगर तुम सो रहे हो तो कैसे जानोगे? अगर वह खड़ा रहकर गर्दन हिलाने लगे तो? उसके सवाल तर्कसंगत हैं, लेकिन वे जीवन की जमीन से कटे हुए हैं। वह बैल को बैल की तरह नहीं, एक चतुर दिमाग की तरह देख रहा है, जो चालाकी से सिस्टम को मात दे सकता है। यहीं तेली और दार्शनिक के बीच असली फर्क उभरता है। तेली जानता है कि बैल क्या है और क्या नहीं है। वह जानता है कि बैल की दुनिया सीमित है, उसकी जरूरतें सीमित हैं और उसकी सोच सरल है। बैल न तो दर्शन करता है, न षड्यंत्र रचता है, न ही व्यवस्था को धोखा देने की योजना बनाता है। तेली का ज्ञान किसी विश्वविद्यालय से नहीं आया, वह रोज़मर्रा के जीवन की धूप, पसीने और मेहनत से उपजा है। यही कारण है कि जब दार्शनिक आखिरी सवाल करता है, तो तेली झुंझलाकर नहीं, बल्कि हंसते हुए जवाब देता है—"यह बैल है, दार्शनिक नहीं।" इस एक वाक्य में जीवन का बड़ा सत्य छिपा है। हम अक्सर हर इंसान, हर व्यवस्था और हर स्थिति को जरूरत से ज्यादा जटिल बना देते हैं। हर जगह चाल, साजिश और चालाकी ढूंढने लगते हैं। तर्क की यह बीमारी हमें यह भूलने पर मजबूर कर देती है कि दुनिया का बड़ा हिस्सा आज भी भरोसे, आदत और सरल व्यवहार से चलता है। अगर हर रिश्ते में, हर काम में और हर व्यवस्था में हम दार्शनिक की तरह सोचने लगें, तो शायद जीवन आगे बढ़ने के बजाय ठहर जाए। यह कथा आधुनिक समय पर भी सटीक बैठती है। आज हम हर व्यक्ति को शक की निगाह से देखते हैं, हर व्यवस्था में खामी ढूंढते हैं और हर काम में धोखे की आशंका पाल लेते हैं। परिणाम यह होता है कि विश्वास खत्म होता चला जाता है और जीवन बोझिल बनता जाता है। तेली हमें याद दिलाता है कि व्यवहारिक बुद्धि भी एक तरह का ज्ञान है, और कई बार वह किताबी तर्क से ज्यादा मजबूत होती है। कहानी यह नहीं कहती कि तर्क बेकार है या दर्शन व्यर्थ है। बल्कि यह बताती है कि तर्क और व्यवहार के बीच संतुलन जरूरी है। जहां जरूरत हो वहां सवाल पूछे जाएं, लेकिन हर जगह सवालों की तलवार लहराना समझदारी नहीं है। बैल से दार्शनिक जैसी चालाकी की उम्मीद करना मूर्खता है, ठीक वैसे ही जैसे हर इंसान को हर समय धोखेबाज़ समझ लेना खुद को मानसिक रूप से थका लेना है। तेली की नींद भी इस कथा में प्रतीक है। वह निश्चिंत होकर सो रहा है, क्योंकि उसे अपने अनुभव पर भरोसा है। दार्शनिक शायद उस जगह होता तो पूरी रात जागकर संभावनाओं की सूची बनाता रहता। एक चैन की नींद सोता, दूसरा अनगिनत सवालों में उलझा रहता। यही जीवन का फर्क है। अंततः यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन को चलाने के लिए हमेशा बड़े सिद्धांतों की जरूरत नहीं होती। कभी-कभी एक घंटी की आवाज़, एक पट्टी और थोड़ा-सा भरोसा ही काफी होता है। और यह समझ कि हर प्राणी दार्शनिक नहीं होता, शायद हमें भी थोड़ी सहजता, थोड़ी सरलता और थोड़ा सुकून दे सकती है।

विद्रूपताओं को अपनाने वाला समाज, नवविवाहिताओं को दहेज की प्रताड़ना झेलनी पड़ती है

कहते हैं, सामाजिक कुप्रथाओं का कोई मजहब नहीं होता। हिंसा की कोई जाति नहीं होती। ये बातें तब फिर सही साबित होती दिखीं, जब हाल में सर्वोच्च न्यायालय ने संवेदनशीलता दिखाते हुए संवैधानिक समानता और सामाजिक असमानता के बीच की गहरी खाई पाटने का प्रयास किया। हाल में अजमल बेग बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में निर्णय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि सामाजिक समस्याएं कभी खत्म नहीं होतीं, बल्कि उन पर समय की गर्द पड़ जाती है और हम कुछ अन्य समस्याओं को समसामयिक और ज्वलंत मानते हुए उनकी चर्चा में उलझ जाते हैं। 1961 में लंबी जद्दोजहद के बाद दहेज प्रतिषेध कानून अस्तित्व में आया और भारतीय दंड संहिता में उसके 25 वर्ष बाद (1986) दहेज हत्या के अपराध को जगह मिली।

हाल के दिनों में कुछ महिलाओं द्वारा दहेज प्रतिषेध कानून के दुरुपयोग के मामलों पर चर्चाओं ने इतना जोर पकड़ा कि हम भूल गए कि आज भी नवविवाहिताओं को दहेज की प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। इस मामले में न्यायालय ने एक तरफ अपने से ऊंचे ओहदे वाले परिवारों में शादी की परंपरा का उल्लेख किया और यह बताना चाहा कि कई बार उसकी कीमत युवा महिलाओं को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। न्यायालय ने यह भी कहा कि जिस मुस्लिम समुदाय में दहेज का कोई प्रविधान ही नहीं है, उलटे जहां 'मेहर' की बात की गई है, उसी समुदाय में किसी महिला को जलाकर मार दिया जाना यह प्रमाणित करता है कि हमारा समाज विद्रूपताओं को अपनाने वाला समाज है। इसमें हम आदर्श से हर वक्त किनारा करते दिखाई देते हैं।

कानूनी प्रविधानों तथा सामाजिक सोच में समानता न होने का प्रमाण हर बार दिखाई देता है। जब देश के विधि निर्माताओं को लगा कि यदि हम महिलाओं को जन्म से ही बराबर मानते हुए उन्हें पैतृक संपत्ति में बराबर का भागीदार बना देंगे तो दहेज की समस्या स्वतः ही खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। या तो पारिवारिक संबंध बचाए रखने के लिए महिलाओं को हलफनामा देना पड़ता है कि वे पैतृक संपत्ति में अपने हक की मांग ही नहीं करेंगी अथवा यदि मांग करेंगी भी तो परिवार स्वेच्छा से उन्हें यह अधिकार नहीं देगा और सर्वोच्च न्यायालय तक अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी।

समाज अभी भी आधी आबादी को बराबरी का पूरा दर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए आज भी दहेज की मांग जारी है और नवविवाहिताओं की हत्या के मामले भी सामने आते हैं। समाज यहीं नहीं रुकता, बल्कि जब एक महिला गर्भधारण करती है तो अनेक घरों में उसके संबंधी यही आस लगाए रहते हैं कि होने वाली संतान बेटा ही हो। पहली संतान के रूप में बेटी फिर भी स्वीकार हो जाती है, लेकिन दूसरी बार विधियों के दुरुपयोग की तलाश प्रारंभ हो जाती है, जो कई बार कन्या भ्रूण हत्या का कारण बनती है। शायद इसी कारण विश्व आर्थिक संगठन ने यह अनुमान लगाया है कि वैश्विक स्तर पर पूर्ण लैंगिक समानता 2150 तक ही आ पाएगी। यानी अभी 125 वर्ष और लगेंगे। क्या तब तक ऐसे ही नवविवाहित महिलाएं प्रताड़ित होंगी और बेटियां गर्भ में मारी जाती रहेंगी? यदि माता-पिता ने समाज से संघर्ष करते हुए उन्हें जन्म दे भी दिया तो क्या वे फिर दहेज की विभीषिका का शिकार होंगी?

दहेज प्रतिषेध कानून एक पंथनिरपेक्ष अधिनियम है और हर पंथ के लोगों पर लागू होता है। यही वजह है कि अजमल बेग के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने एक साथ अनेक दिशानिर्देश जारी किए हैं। मसलन, स्कूली पाठ्यक्रम में ऐसे बदलाव किए जाएं, जिनसे लैंगिक रूढ़िवादिता समाप्त हो। आरंभ से संदेश जाए कि विवाह में दोनों पक्ष समान हैं और कोई भी दूसरे के अधीन नहीं है। यह संवैधानिक समानता की भावना जब तक सामाजिक समानता के धरातल पर चरितार्थ नहीं होगी, तब तक हम पूर्ण न्याय पाने की स्थिति में नहीं होंगे।

सभी राज्यों में न केवल दहेज निषेध अधिकारियों की प्रभावी नियुक्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए, बल्कि उनके नाम, फोन नंबर और ई-मेल जैसी जानकारी स्थानीय स्तर पर व्यापक रूप से प्रसारित करने के साथ उन्हें संवेदनशील बनाया जाना चाहिए। महिला एवं बाल कल्याण अधिकारियों के साथ-साथ पुलिस और न्यायिक अधिकारियों को भी प्रशिक्षित किया जाए, ताकि दहेज मृत्यु और क्रूरता के मामलों के सामाजिक-मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समग्रता में समझा जा सके और वास्तविक मामलों तथा झूठे अथवा दुरुपयोग वाले मामलों में अंतर किया जा सके।

इसी कारण सभी उच्च न्यायालयों को भी निर्देश दिया गया है कि वे दहेज मृत्यु और दहेज प्रताड़ना से जुड़े लंबित मामलों की समीक्षा कर उनके शीघ्र निपटारे के लिए प्रभावी कदम उठाएं। इसका तात्पर्य यह है कि समाज का हर परिवार अपने बच्चों को शिक्षा दे, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करे और समानता के मजबूत ताने-बाने के साथ विवाह जैसे रिश्ते की बुनियाद डाले, ताकि पूरे समाज को यह संदेश मिले कि विवाह एक सामाजिक संस्था है और मातृत्व एक सामाजिक जिम्मेदारी। गृहस्थी की गाड़ी एक पहिये पर नहीं चल सकती, बल्कि हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। एक सुलझे हुए परिवार में ही एक सुलझा हुआ समाज बसता है।

अभियान

जब ईश्वर स्वयं भक्त बनकर प्रेम का रहस्य जानने उतरे

भक्ति परंपरा में राधा और कृष्ण का संबंध केवल प्रेम कथा नहीं है, वह ईश्वर और आत्मा के बीच के सबसे सूक्ष्म, सबसे गहन और सबसे मधुर रिश्ते की अभिव्यक्ति है। यह वह प्रेम है जिसमें अधिकार नहीं, अपेक्षा नहीं, केवल समर्पण है। यही कारण है कि राधा-कृष्ण के संवाद साधारण शब्दों में होते हुए भी अनंत अर्थ समेटे रहते हैं। ऐसा ही एक प्रसंग निकुञ्ज में घटित हुआ, जिसने आगे चलकर कलियुग के सबसे रहस्यमय और करुण अवतार की नींव रखी।

एक दिन राधा जी श्रीकृष्ण से मिलने निकुञ्ज में आईं। वातावरण में वही अलौकिक शांति थी, जिसमें पत्तों की सरसराहट भी मानो कोई राग छेड़ रही हो। यमुना की लहरें धीमे स्वर में बह रही थीं और वृंदावन की हवा प्रेम से भीगी हुई थी। राधा जी ने कृष्ण की ओर देखा, जिनके हाथ में बांसुरी थी, और सहज भाव से पूछ बैठीं, "तुम बांसुरी क्यों बजाते हो?" यह प्रश्न सरल था, लेकिन इसके पीछे राधा का पूरा हृदय छिपा हुआ था।

कृष्ण ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, "तुम्हें बुलाने के लिए।" यह उत्तर सुनते ही राधा का मन भर आया। उन्होंने कहा, "जब तुम बांसुरी बजाते हो, तब मैं सब कुछ भूल जाती हूं। घर, संसार, लोक-लाज, कर्तव्य—सब पीछे छूट जाता है। मैं सोचती भी नहीं, बस तुम्हारी ओर खिंची चली आती हूं।" यह कहना मात्र नहीं था, यह उस प्रेम की स्वीकारोक्ति थी, जिसमें स्वयं का अस्तित्व भी तिरोहित हो जाता है।

कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, "ऐसा क्या है मेरी इस बांसुरी में?" राधा ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, "कृष्ण, तुम यह प्रेम और यह विरह कभी नहीं समझ पाओगे। अगर तुम राधा होते, तभी जान पाते।" यह वाक्य किसी चुनौती की तरह नहीं था, बल्कि एक सत्य की घोषणा थी। प्रेम का अनुभव केवल वही कर सकता है, जो प्रेम में डूबा हो। ईश्वर होकर भी कृष्ण इस अनुभूति से अछूते थे, क्योंकि वे प्रेम के विषय थे, प्रेम के भोक्ता नहीं।

कृष्ण के भीतर एक अद्भुत जिज्ञासा जाग उठी। उन्होंने पूछा, "यदि मैं राधा होता और तुम कृष्ण होतीं, तो क्या करतीं?" राधा जी का उत्तर और भी गूढ़ था। उन्होंने कहा, "फिर जब मैं तुम्हें अपने विरह में तड़पते देखती, तब मुझे भी तुम्हारी तरह अत्यंत आनंद की अनुभूति होती।" यह सुनकर कृष्ण समझ गए कि प्रेम का सर्वोच्च रस मिलन में नहीं, बल्कि विरह में छिपा है। यह वह रस है, जिसमें पीड़ा भी आनंद बन जाती है।

यहीं से ईश्वर के भीतर एक अद्भुत संकल्प का जन्म हुआ। कृष्ण ने स्वीकार किया कि उनके भीतर तीन इच्छाएं हैं, जो अब तक अधूरी हैं। पहली इच्छा यह जानने की कि राधा का उनके प्रति जो प्रेम है, वह वास्तव में कैसा है। वह प्रेम, जो किसी शर्त पर नहीं टिका, जो स्वयं भगवान को भी बांध लेता है। दूसरी इच्छा यह समझने की कि उस प्रेम के माध्यम से राधा उनके जिस माधुर्य का आस्वादन करती हैं, वह माधुर्य वास्तव में कितना गहरा और दिव्य है। और तीसरी इच्छा यह अनुभव करने की कि उनके माधुर्य के आस्वादन से राधा को जो सुख प्राप्त होता है, वह सुख कैसा है, उसकी अनुभूति कैसी होती है।

कृष्ण ने राधा से कहा, "इन तीनों इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए मैं कलियुग में अवतार लूंगा। मेरा शरीर कृष्ण का होगा, लेकिन मेरा अंतःकरण राधा का होगा। मैं राधाभाव लेकर अवतरित होऊंगा।" यह कोई साधारण घोषणा नहीं थी। यह वह क्षण था, जब भगवान ने स्वयं भक्त बनने का निश्चय किया।

कलियुग में वही संकल्प श्रीचैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुआ। बाहरी रूप से वे कृष्ण थे, लेकिन भीतर से वे राधा थे। उनके नेत्रों से अश्रु बहते थे, उनका हृदय विरह से भरा रहता था और उनके मुख से निरंतर "कृष्ण" नाम का कीर्तन निकलता था। यह पहली बार था, जब भगवान स्वयं अपने नाम का जप कर रहे थे। यह बताने के लिए कि नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, और प्रेम का मार्ग ही सबसे सरल और सबसे गहरा मार्ग है।

चैतन्य महाप्रभु का जीवन प्रेम का जीवंत उदाहरण बन गया। वे न ज्ञान का उपदेश देते थे, न कर्मकांड का। वे केवल प्रेम सिखाते थे—ऐसा प्रेम, जिसमें अहंकार गल जाता है, जिसमें स्वयं का अस्तित्व मिट जाता है। वे कभी हंसते थे, कभी रोते थे, कभी कृष्ण के विरह में मूर्छित हो जाते थे। यह सब राधाभाव की अभिव्यक्ति थी। वही भाव, जिसे कृष्ण वृंदावन में समझ नहीं पाए थे, उसे वे अब स्वयं जी रहे थे।

इस कथा का गूढ़ अर्थ यही है कि प्रेम में कोई छोटा-बड़ा नहीं होता। यहां तक कि ईश्वर भी जब प्रेम को पूरी तरह जानना चाहते हैं, तो उन्हें भक्त बनना पड़ता है। राधा का प्रेम इतना ऊंचा है कि स्वयं भगवान उसे समझने के लिए अवतार लेते हैं। यह भक्ति परंपरा का शिखर है, जहां भक्त भगवान से बड़ा हो जाता है, और भगवान भक्त के चरणों में बैठकर प्रेम सीखते हैं। राधा और चैतन्य का यह संबंध हमें यह भी सिखाता है कि प्रेम अधिकार नहीं, अनुभव है। प्रेम पाने की वस्तु नहीं, खो जाने की अवस्था है। जब सब कुछ खो जाता है, तभी प्रेम पूर्ण होता है। राधा ने यही किया और कृष्ण ने वही अनुभव करने के लिए चैतन्य रूप धारण किया।

यह कथा आज भी उतनी ही जीवंत है, जितनी उस समय थी। हर वह हृदय जो ईश्वर को पाना चाहता है, इस कथा में अपना मार्ग खोज सकता है। ज्ञान से ईश्वर समझे जा सकते हैं, कर्म से पूजा जा सकती है, लेकिन प्रेम से ही ईश्वर जिए जा सकते हैं। यही राधा का संदेश है, यही चैतन्य का अवतार है और यही कृष्ण की अधूरी इच्छाओं की पूर्णता है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH

अटल नेतृत्व, अविरत विकास : सुशासन से समृद्ध किसान

किसान सूर्योदय योजना (केएसवाई) अंतर्गत राज्य के 98 प्रतिशत से अधिक गाँवों को मिल रही है दिन में बिजली, 19 लाख से अधिक किसान प्राप्त कर रहे हैं दिन में बिजली का लाभ

- वर्ष 2026-27 में जेटको द्वारा 1000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 5 नए सबस्टेशन बनाने तथा लगभग 1100 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) के ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत बनाने की योजना
- 40 नए सब स्टेशनों, 4640.73 सीकेएम की ट्रांसमिशन लाइन्स तथा 3927.72 सीकेएम के एमवीसीसी कार्य के लिए राज्य सरकार द्वारा 5000 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च
- मार्च-2026 तक राज्य के सभी किसानों को सिंचाई के दिन में बिजली मिलने लगेगी : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

(जीएनएस)। गांधीनगर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सुशासन का उद्देश्य किसानोन्मुखी योजनाओं और पहलों को पारदर्शी एवं प्रभावी ढंग से किसानों तक पहुँचाना है। किसान भारत की रीढ़ हैं और भारत का विकास तभी संभव है; जब किसान समृद्ध, सुरक्षित एवं आत्मनिर्भर हों। गुजरात में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के सुदृढ़ सुशासन अंतर्गत राज्य सरकार किसानोन्मुखी योजनाएँ सभी किसानों तक सफलतापूर्वक पहुँचा रही है और इसका श्रेष्ठ उदाहरण है किसान सूर्योदय योजना (केएसवाई), जिसके जरिये आज राज्य के 17,018 गाँवों यानी 98.66 प्रतिशत गाँवों को दिन में बिजली का लाभ मिल रहा है। इस योजना अंतर्गत गुजरात के 19.69 लाख किसानों को दिन में बिजली मिलने लगी है। किसानों को दिन में विद्युत आपूर्ति करने की गुजरात की सफलता के विषय में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल कहते हैं, "प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की कृषि हितकारी नीतियों एवं किसानों के प्रति संवेदना के कारण आज राज्य के लगभग 98 प्रतिशत किसानों को दिन में बिजली मिलने लगी है। जो बाकी हैं, उन्हें भी मार्च-2026 दिन में बिजली मिलने लगेगी और यह मिशन पूरा किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री का यह एक बहुत बड़ा निर्णय था, जिसे हम पूरा कर सके। यह हम सबके लिए आनंद की बात है। किसानों को पर्याप्त पानी तथा बिजली मिलने के कारण राज्य के कृषि क्षेत्र की तसवीर समग्रतया बदल गई है और किसान समृद्ध हुए हैं।"

किसान सूर्योदय योजना अंतर्गत सूर्य प्रकाश के घण्टों का अधिकतम् उपयोग हो; इस प्रकार किसानों को बिजली दी जाती है

किसान सूर्योदय योजना (केएसवाई) वर्ष 2020 में लागू की गई थी, जिसका उद्देश्य सुबह 5 से रात 9 बजे तक दो स्लॉट में (सुबह 5 से दोपहर 1 बजे तक का स्लॉट तथा दोपहर 1 से रात 9 बजे तक का स्लॉट) में विद्युत आपूर्ति करना था। हालाँकि योजना लागू किए जाने के बाद कृषि क्षेत्र के लिए विद्युत आपूर्ति की समयसारिणी को सूर्य प्रकाश के घण्टों के हिसाब से अधिक कार्यक्षम बनाया जाना आवश्यक प्रतीत हुआ, जिससे सिंगल शिफ्ट का कॉन्सेप्ट प्रकाश में आया। इस कॉन्सेप्ट के तहत किसानों को सूर्य प्रकाश के घण्टों के दौरान; विशेषकर सुबह 7 से शाम 5 बजे तक कृषि के लिए बिजली पहुँचाई जाती है। सौर ऊर्जा को इस प्रकार एकीकृत किए जाने से अधिक मांग की समयावधि के दौरान ग्रिड पर लोड कम होता है, जिससे कृषि के लिए टिकाऊ एवं विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होती है। हाल में इस योजनांतर्गत राज्य के 17,018 गाँवों (98.66 प्रतिशत) को दिन में बिजली पहुँचाई जा रही है और राज्य के 98 प्रतिशत सबस्टेशनों को डे-टाइम यानी दिन के समय में शिफ्ट किया गया है। शेष 231 गाँवों को इस योजनांतर्गत लाने के लिए शेष 45 रोटेशनल सबस्टेशनों की शिफ्टिंग का कार्य प्रगत्याधीन है। उल्लेखनीय है कि इस योजनांतर्गत 40 नए सबस्टेशन स्थापित करने, 4640.73 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) की ट्रांसमिशन लाइनें डालने और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 3927.72 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) के एमवीसीसी कार्य के लिए राज्य सरकार द्वारा 5353.62 करोड़ रुपए का कुल खर्च किया गया है।

दिन में बिजली मिलने से जानवरों का भय दूर हुआ, समय की भी बहुत बचत हुई : किसान सूर्योदय योजना के लाभार्थी

हिम्मतनगर तहसील के काँकरोल गाँव के किसान श्री जयेश पटेल, जो हिम्मतनगर मंडी के अध्यक्ष भी हैं, कहते हैं, "पहले किसानों को रात में बिजली मिलती थी, जिसके कारण रात में पानी छोड़ने जाने में तकलीफ होती थी। पानी का व्यय भी बहुत होता था और रात में जानवरों का भी डर रहता था। अब किसान सूर्योदय योजना अंतर्गत पिछले 2 वर्षों से हमें दिन में बिजली मिलती है, जिसके माध्यम से इन सभी समस्याओं का निवारण आ गया है। अब किसानों को खेतों में उचित समय पर उचित मात्रा में पानी मिल जाता है और समय की भी बचत होती है। इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का समग्र हिम्मतनगर तहसील के किसानों की ओर से आभार मानता हूँ।" उल्लेखनीय है कि किसान सूर्योदय योजना के क्रियान्वयन से किसानों को दिन में बिजली मिलने के कारण वे दिन के दौरान उचित समय पर खेत में अच्छी तरह सिंचाई कर पाते हैं और अधिक फसल उत्पादन प्राप्त कर पाते हैं, जो किसानों की आर्थिक समृद्धि में परिणामित होता है। ट्रांसमिशन इन्फ्रास्ट्रक्चर के निरंतर सुदृढ़ीकरण के साथ राज्य सरकार किसान सूर्योदय योजना का चरणबद्ध क्रियान्वनय जारी रखेगी, जो दिन के समय विश्वसनीय एवं टिकाऊ विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करेगा।

वर्ष 2026-27 में नए सबस्टेशन स्थापित करने तथा ट्रांसमिशन नेटवर्क मजबूत करने की योजना

वर्ष 2026-27 में दिन के दौरान कृषि विद्युत आपूर्ति के लिए गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन (जेटको) ने लगभग पाँच सबस्टेशनों तथा 1100 सीकेएम ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत बनाने की योजना है, जिसका अनुमानित खर्च 1000 करोड़ रुपए है। इसके अतिरिक्त; वर्ष 2026-27 में डिसकॉम के लिए एबी केबल/एमवीसीसी डालने का अनुमानित खर्च 375 करोड़ रुपए है।

"द यश मंगलम शो" की नई लघु फिल्म "द लीगेसी ऑफ मैथेमेटिक्स" गणित के जादूगर रामानुजन को समर्पित','"राष्ट्रीय गणित दिवस" पर हुआ लघु फिल्म का लोकार्पण'

(जीएनएस)। मुंबई। इंटरनेट के लोकप्रिय माध्यम यू-ट्यूब पर पिछले दिनों जारी विभिन्न लघु फिल्मों को मिली निरंतर सफलता के बाद सृजनात्मक उत्कृष्टता के एक सशक्त ब्रांड के रूप में लोकप्रिय होते जा रहे *"द यश मंगलम शो"* की नवीनतम कड़ी के रूप में लघु फिल्म *"द लीगेसी ऑफ मैथेमेटिक्स"* का लोकार्पण राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर 21 दिसम्बर, 2025 को बिहार सरकार के कला एवं संस्कृति विभाग के अंतर्गत बिहार फिल्म विकास निगम के मुख्य सलाहकार अरविंद रंजन दास द्वारा किया गया। इस लघु फिल्म में गणित के जादूगर श्रीनिवास रामानुजन के विलक्षण व्यक्तित्व और कृतित्व का सुरुचिपूर्ण विश्लेषण किया गया है।

एक अनूठी सृजनात्मक पहल के अंतर्गत *"वाइब्रेशन्स मीडिया वर्क्स, मुंबई"* द्वारा *"मगध एकेडमी ऑफ कल्चर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स" MACPA* के बैनर तले नवसृजित यह अद्भुत लघु फिल्म

"द लीगेसी ऑफ मैथेमेटिक्स" सोशल मीडिया के सबसे सशक्त प्लेटफॉर्म यू-ट्यूब पर एक सुरुचिपूर्ण चैनल *"द यश मंगलम शो-2025'* के अंतर्गत अपलोड की गई है, जो अपने अनूठे कंटेंट और प्रस्तुतीकरण के विलक्षण अंदाज़ के लिए काफी लोकप्रिय है और व्यापक तौर पर सराहा जाता रहा है। इससे पहले इस लोकप्रिय शो की *"धरोहरः ए पोएटिक सागा"*, *"शिल्पकार"*, *"योगा रिट्रीट", "सेहत के रखवाले", *कारगिल विजय दिवस- ए पोएटिक सागा*, *"मैं भारत हूँ..!"* और *"पथ प्रदर्शक"* जैसी प्रभावशाली कड़ियाँ यू-ट्यूब पर काफी अच्छा प्रतिसाद पा चुकी हैं। इस शो के जोशीले प्रस्तुतकर्ता यश मंगलम हैं, जो सिर्फ़ 15 वर्ष की आयु में ही सशक्त प्रस्तुतीकरण से अपनी दमदार शैली की बदौलत शो- बिज़ की दुनिया में अपना अच्छा मुक़ाम हासिल कर रहे हैं। इस विशेष लघु फिल्म का प्रभावशाली लेखन मुंबई के सुपरिचित गीतकार, मंच संचालक तथा मीडिया एवं जनसम्पर्क सलाहकार गजानन महतपुरकर ने किया है, जिसमें गणित के जादूगर श्रीनिवास रामानुजन के जीवन के विभिन्न पहलुओं को बखूबी पिरोया गया है। उल्लेखनीय है कि गजानन महतपुरकर द्वारा लिखी गई 10 से अधिक लघु फिल्में पहले ही यू-ट्यूब पर धूम मचा चुकी हैं। इसी क्रम में अब नवीनतम लघु फिल्म के ज़रिये गजानन महतपुरकर की सशक्त लेखनी और सुप्रसिद्ध फिल्म निर्देशक एवं एडिटर अनुपम मंगलम के कुशल निर्देशन का कमाल यू-ट्यूब पर लोकप्रिय हो रहा है। इस लघु फिल्म के प्रोड्यूसर बिहार के प्रमुख शिक्षाविद लायन राजीव भार्गव हैं। इस सशक्त, प्रभावशाली और संवेदनशील लघु फिल्म को कुशल निर्देशन के जरिये पर्दे पर उतारने का दायित्व बखूबी निभाया है, मुंबई के विज्ञापन एवं फिल्म जगत के भरोसेमंद निर्देशक अनुपम मंगलम ने, जिनको पिछले 25 सालों में 300 से ज्यादा विज्ञापन फिल्में बनाने का समृद्ध अनुभव प्राप्त है। इस नवसृजित लघु फिल्म का भावपूर्ण संगीत समीर पखाले ने दिया है। वीडियोग्राफी श्रीकांत, वी एफ एक्स संयोजन गिनीलाल सालुंके, एडिटिंग प्रताप शिंदे, डिज़ाइनिंग एलेक्स बेकर और कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग कला मंगलम द्वारा सुनिश्चित की गई है। पटना के मशहूर गणितज्ञ आनंद कुमार को समर्पित और टेंडर हार्ट्स इंटरनेशनल स्कूल, पटना द्वारा प्रायोजित इस लघु फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन वाइब्रेशन्स मीडिया वर्क्स, मुंबई ने किया है। महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय गणित दिवस के उपलक्ष्य में निर्मित इस लघु फिल्म का लोकार्पण और प्रीमियर शो का उद्घाटन बिहार फिल्म विकास निगम के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर अरविंद रंजन दास द्वारा 21 दिसम्बर , 2025 को पटना के टेंडर हार्ट्स इंटरनेशनल स्कूल के सभागार में किया गया। इस अवसर पर दीप प्रज्वलन के दौरान विद्यालय की प्रधानाध्यापिका एवं लॉयंस क्लब, पटना की अध्यक्ष शिवानी भार्गव और सचिव लॉयन रोहित शंकर सहित अन्य गणमान्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस लघु फिल्म में टेंडर हार्ट्स इंटरनेशनल स्कूल के विद्यार्थियों ने भी अभिनय किया है। लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर अरविंद रंजन दास उपस्थित रहे। अन्य प्रमुख अतिथियों में लॉयंस क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर प्रदीप खेतान, लॉयन रचना खेतान, डॉ. रवि भार्गव, बिहार स्टेट पावरलिफ्टिंग एसोसिएशन के अशोक मेहता, राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी योगेश गुप्ता, पटना के प्रमुख समाजसेवी नीरज गुप्ता, जाने-माने बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. श्रवण कुमार , डॉ. चिरंजीव दुबे , लायन सोनिया, बाटा के पूर्व HR निदेशक ऋषिकेश मुख्य रूप से शामिल हैं। यह लघु फिल्म इस यू-ट्यूब लिंक पर देखी जा सकती है :-

भावनगर मंडल में टिकट चेकिंग से एकल EFT के माध्यम से अब तक की सर्वाधिक वसूली

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे, भावनगर मंडल के अंतर्गत टिकट जांच के दौरान एक सराहनीय एवं ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की गई है। श्री राजन कुमार सिंह, मुख्य टिकट निरीक्षक(CTI)/वेरावल, ने टी.एन.सी.आर. के रूप में गाड़ी संख्या 12945 (वेरावल–बनारस एक्सप्रेस) के अपर क्लास में कार्य करते हुए 3AC कोच B2 एवं B4 में यात्रियों की जांच के दौरान गंभीर अनियमितता का पता लगाया।

भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया की गहन चेकिंग के बाद यह पाया गया कि 54 यात्रियों के ग्रुप में 36 यात्री बिना वैध टिकट अथवा अन्य व्यक्तियों के नाम पर यात्रा कर रहे थे। श्री राजन कुमार सिंह ने अत्यंत सूझबूझ, धैर्य एवं कुशल व्यवहार के साथ यात्रियों से बातचीत कर रेलवे नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की तथा 78,060/- (अठहत्तर हजार साठ रुपये मात्र) की रेलवे देय राशि की सफलतापूर्वक वसूली की।

उल्लेखनीय है कि श्री राजन कुमार सिंह दिव्यांग (श्रवण बाधित) हैं और इसके बावजूद उन्होंने ट्रेन में एकल रूप से कार्य करते हुए यह पूरी कार्रवाई स्वयं संपन्न की। उनका यह कार्य न केवल कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी का उदाहरण है, बल्कि अन्य रेलकर्मियों के लिए भी प्रेरणास्रोत है। यह उपलब्धि इसलिए भी विशेष है क्योंकि भावनगर मंडल में अब तक किसी भी टीटीई द्वारा एकल लेन-देन (Single EFT) में की गई यह सर्वाधिक वसूली है। मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने कहा की रेल प्रशासन श्री राजन कुमार सिंह के इस उत्कृष्ट, साहसिक एवं अनुकरणीय कार्य के लिए उन्हें हार्दिक बधाई देता है तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है।

24 से 30 दिसंबर तक साबरमती-खोडियार के बीच,स्थित रेलवे क्रॉसिंग नं. 240 (त्रागढ रोड फाटक) बंद रहेगा

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल पर साबरमती-खोडियार स्टेशनों के बीच स्थित रेलवे क्रॉसिंग नं. 240 किमी 773/4-6 (त्रागढ़ रोड फाटक) 24 दिसंबर, 2025 को प्रातः 08.00 बजे से 30 दिसंबर, 2025 को प्रातः 08.00 बजे तक मरम्मत कार्य (AMC रोड एप्रोचिंग और हाइट गेज कार्य) हेतु 7 दिन बंद रहेगा।

सड़क उपयोगकर्ता इस अवधि के दौरान रेलवे क्रॉसिंग नंबर 241 अंडरपास वाया गोदरेज गार्डन सिटी और एस. जी. हाईवे से आवागमन कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के करकमलों से मंगलवार को गुजरात पुलिस के 11,607 नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे

गांधीनगर स्थित रामकथा मैदान में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी तथा राज्य मंत्री श्री कमलेशभाई पटेल की प्रेरक उपस्थिति रहेगी

(जीएनएस)। गांधीनगर : गुजरात सरकार के गृह विभाग द्वारा राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के आशय से लोकरक्षक कैडर की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की गई है। इस भर्ती अंतर्गत चयनित हजारों युवा उम्मीदवारों के लिए 23 दिसंबर, 2025 मंगलवार को गांधीनगर में सेक्टर-11 स्थित रामकथा मैदान में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के करकमलों से तथा उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी की प्रेरक उपस्थिति में भव्य 'चयन (नियुक्ति) पत्र प्रदान' कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।

इस अवसर पर पुलिस आवास एवं जेल राज्य मंत्री श्री कमलेशभाई पटेल विशेष रूप से उपस्थित रहकर नवनियुक्त जवानों को प्रोत्साहित करेंगे। लोकरक्षक कैडर में कुल 11,899 उम्मीदवारों की भर्ती प्रक्रिया की गई थी, जिनमें 8,782 पुरुष एवं 3,117 महिला उम्मीदवारों का चयन किया गया है। फिलहाल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूर्ण कर चुके 11,607 उम्मीदवारों को इस कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के साथ ही राज्य सरकार द्वारा पुलिस बल में शेष 13,591 रिक्तियों के लिए भी नया विज्ञापन प्रकाशित कर दिया गया है। यह नई भर्ती प्रक्रिया भी हाल में कार्यरत है, जो दर्शाता है कि राज्य सरकार युवाओं को पारदर्शी ढंग से सरकारी सेवा में जोड़ने का अवसर प्रदान करने के लिए दृढ़ है। इस कार्यक्रम में राज्य के मुख्य सचिव श्री एम. के. दास, राज्य पुलिस महानिदेशक श्री विकास सहाय, पुलिस भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष डॉ. नीरजा गोटरू सहित उच्चाधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।

कानून से ऊपर कोई नहीं, भीड़तंत्र को नहीं मिलेगी छूट : मुख्यमंत्री विजयन

(जीएनएस)। तिरुअनंतपुरम। केरल के पलक्कड़ जिले में सामने आए कथित मॉब लिंचिंग के मामले ने एक बार फिर पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। वालयार के कीजक्के अत्तापल्लम क्षेत्र में मूल रूप से छत्तीसगढ़ निवासी रामनारायण की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने न सिर्फ कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि समाज के भीतर पनप रही भीड़ मानसिकता की भयावह तस्वीर भी सामने ला दी है। इस घटना पर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा है कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री विजयन ने इस घटना को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और अमानवीय करार देते हुए कहा कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि केरल जैसी प्रगतिशील और साक्षरता में अग्रणी राज्य में इस तरह की घटनाएं स्वीकार्य नहीं हैं। विजयन ने भरोसा दिलाया कि पुलिस की एक विशेष जांच टीम इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और जो भी लोग इस घटना में शामिल पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

महाप्रबंधक, पश्चिम रेलवे ने वडोदरा मंडल के दो कर्मचारियों को संरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया

(जीएनएस)। रेलवे के संचालन में संरक्षा सर्वोपरि होती है और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक कर्मचारी की सजगता एवं सतर्कता अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता ने वडोदरा मंडल के दो रेल कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए संरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया। ये पुरस्कार नवम्बर 2025 के दौरान ड्यूटी पर रहते हुए सतर्कता दिखाने और संभावित दुर्घटनाओं को समय रहते टालने में अहम भूमिका निभाने के लिए प्रदान किए गए।

पुरस्कार प्राप्त करने वाले कर्मचारी (1) श्री नंदन कुमार ठाकुर, पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के पखाजन में स्टेशन मास्टर,के पद पर कार्यरत हैं।दिनांक 22.11.2025 को, अपने स्टेशन से लगभग 19:15 बजे गुड्स ट्रेन के गुजरते समय, उन्होंने ब्रेक बाइंडिंग की स्थिति देखी, जो लाल तपे पहिये और जलने की गंध से स्पष्ट थी। तत्परता और सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दशति हुए उन्होंने तुरंत लोको पायलट एवं ट्रेन मैनेजर को VHF संचार के माध्यम से सूचित किया। उनकी समय पर दी गई सूचना के आधार पर ट्रेन को रोका गया, समस्या की जाँच की गई तथा ब्रेक बाइंडिंग की समस्या का सफलतापूर्वक निवारण किया गया। उनकी सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से एक संभावित दुर्घटना टल गई तथा ट्रेन संचालन सुरक्षित रूप से सुनिश्चित हो सका।

(2) श्री मुकराज मीणा 'गोधरा' में लोको पायलट (मालगाड़ी), के पद पर कार्यरत हैं। दिनांक 14.10.2025 को, गोधरा से गुड्स ट्रेन पर काम करते समय, ववादी खुर्द –टिम्बा रोड के बीच, लोको पायलट ने देखा कि OHE तार टूटी हुई अवस्था में लटका हुआ था। अत्यधिक सतर्कता और सूझबूझ के साथ उन्होंने तुरंत इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन दबाया, पेंटोग्राफ को नीचे किया और फ्लैशर लाइट चालू की, जिससे ट्रेन सुरक्षित रूप से रुक गई। इसके बाद उन्होंने स्टेशन मास्टर- टिम्बा रोड और TRD स्टाफ के माध्यम से TLC/CTO को सूचित किया, जिन्होंने आकर पुष्टि की कि OHE स्टे ट्यूब इंसुलेटर टूटा हुआ था। सुधार के बाद, सेक्शन को आगे की आवाजाही के लिए तैयार कर दिया गया।उनकी पैनी नज़र, समय पर की गई कार्रवाई और त्वरित निर्णय के कारण, पेंटोग्राफ और OHE को और अधिक नुकसान से सफलतापूर्वक बचा लिया गया, जिससे लोकोमोटिव की सुरक्षा और निर्बाध ट्रेन आवाजाही सुनिश्चित हुई।

महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता ने पुरस्कार प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की सतर्कता की सराहना करते हुए कहा कि ये सभी कर्मचारी अपने कार्य के प्रति समर्पित रहकर दूसरों के लिए प्रेरणास्रोत बने हैं।

पश्चिम रेलवे को अपने ऐसे कर्मचारियों पर गर्व है, जो विषम परिस्थितियों में भी धैर्य और समझदारी के साथ कार्य करते हैं और रेल संचालन की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। यह सम्मान न केवल उनके व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना है, बल्कि यह पश्चिम रेलवे की उस संस्कृति को भी प्रतिबिंबित करता है, जहाँ संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है।

पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक ने अहमदाबाद मंडल के तीन कर्मचारियों को संरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता ने पश्चिम रेलवे मुख्यालय, मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में अहमदाबाद मंडल के तीन कर्मचारियों को उत्कृष्ट कार्य, सतर्कता एवं सुरक्षित ट्रेन संचालन में महत्वपूर्ण योगदान के लिए "मैन ऑफ द मन्थ" (नवंबर–2025) संरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया। सम्मानित कर्मचारी है—

1. श्रीमती भावना साकरे, वरिष्ठ सहायक लोको पायलट, साबरमती दिनांक 28.11.2025 को श्रीमती भावना साकरे - ट्रेन संख्या AFGB/MIGK पर लोको संख्या 50001 के साथ ड्यूटी पर थीं। सुबह लगभग 09:05 बजे साबरमती यार्ड में सिग्नल S12 पर खड़ी ट्रेन के पास से 'रेल स्पेशल रतनगढ़' (लोको संख्या 60386) गुजर रही थी। इस दौरान उन्होंने चार स्थानों पर रेल पटरी (LWR) में खिसकाव देखा, जो अत्यंत जोखिमपूर्ण था। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने तुरंत वॉकी-टॉकी के माध्यम से संबंधित लोको पायलट एवं ट्रेन मैनेजर से संपर्क कर ट्रेन को रुकवाया। निरीक्षण में पटरी असुरक्षित पाई गई, जिससे समय रहते संभावित पटरी से उतरने, बड़े हादसे तथा जान-माल के नुकसान को टाल दिया गया।

2. श्री कृष्ण कुमार, टेक्नीशियन ग्रेड–II, अहमदाबाद
दिनांक 08.11.2025 को ट्रेन संख्या 19412 के लिए लोको संख्या 22392 का ट्रिप निरीक्षण किया जा रहा था। ELS/अहमदाबाद में रूफ एवं ग्रेविटी वर्क सेंटर पर कार्यरत श्रीकृष्ण कुमार ने सूक्ष्म निरीक्षण के दौरान पीटी-2 लोअर आर्म का बेयरिंग बोल्ट टूटी अवस्था में पाया। उनकी सतर्कता एवं गहन जांच से संभावित लोको विफलता, ट्रेन डिटेंशन तथा ओएचई को होने वाले नुकसान को समय रहते रोका जा सका।

3. श्री भूपेन्द्र सिंह राठौर, ट्रेक मेंटेनर, साणंद
श्री भूपेन्द्र सिंह राठौर, SSE/P. Way/साणंद के अंतर्गत गैंग नंबर–05 में ट्रेक मेंटेनर के रूप में कार्यरत हैं। दिनांक 02.11.2025 को LC संख्या–29 (छारोडी–साणंद के बीच) पर गेटमैन ड्यूटी के दौरान उन्होंने ट्रेन संख्या 16333 से धुआँ निकलते देखा। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए उन्होंने तुरंत लाल झंडा दिखाकर ट्रेन रुकवाई। आवश्यक कार्रवाई के पश्चात ब्रेक ब्लॉक रिलीज किए जाने पर ट्रेन को सुरक्षित रूप से आगे रवाना किया गया।

अहमदाबाद मंडल को अपने ऐसे कर्मठ, सजग और जिम्मेदार कर्मचारियों पर गर्व है। यह सम्मान न केवल उनकी कर्तव्यपरायणता की सराहना है, बल्कि पश्चिम रेलवे की उस कार्य-संस्कृति का भी प्रतीक है, जिसमें संरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।

कुपोषण पर कटौती, वीआईपी शानो-शौकत पर करोड़ों का खर्च: गुजरात से उठे सवालों ने सरकार की प्राथमिकताओं को कठघरे में खड़ा किया

(जीएनएस)। नई दिल्ली। गुजरात में आदिवासी समाज की बदहाली और सरकारी प्राथमिकताओं को लेकर आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि एक ओर सरकार प्रधानमंत्री और वीआईपी कार्यक्रमों पर बिना झिझक करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, वहीं दूसरी ओर आदिवासी बच्चों, कुपोषितों, छात्रों और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए फंड की कमी का बहाना बनाकर जिम्मेदारी से बच रही है। आप नेताओं ने इसे केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि आदिवासी समाज के प्रति सरकार की असंवेदनशील और विरोधी मानसिकता बताया।

अनुराग ढांडा ने कहा कि गुजरात में आदिवासी समाज के नाम पर बड़े-बड़े आयोजन होते हैं, मंच सजते हैं, भाषण दिए जाते हैं और तस्वीरें खिंचवाई जाती हैं, लेकिन जब असल ज़मीनी समस्याओं की बात आती है तो सरकार का खजाना अचानक खाली हो जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि आदिवासी बच्चों की छात्रवृत्तियां रोकी गई हैं, सिकल सेल जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज के लिए पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही और आंगनवाड़ी केंद्रों के बिल महीनों से अटके पड़े हैं। ढांडा ने सवाल उठाया कि यदि सरकार के पास वीआईपी इंतज़ामों, मंचों और डोम के लिए असीमित धन है, तो वही सरकार आदिवासी बच्चों की पढ़ाई और सेहत के लिए पैसा क्यों नहीं जुटा पा रही।

दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भी सरकार की नीतियों पर तीखा प्रहार करते हुए इसे “दिखावटी विकास” करार दिया। उन्होंने कहा कि आदिवासी इलाकों में कुपोषण, शिक्षा की कमी और स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव आज भी गंभीर समस्या बना हुआ है, लेकिन सरकार की प्राथमिकताएं ज़मीनी हकीकत से कोसों दूर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार की असली चिंता मंचों की भव्यता, डोम की सजावट और वीआईपी मेहमानों की सुविधाओं तक सीमित रह गई है, जबकि आदिवासी समाज को केवल भाषणों और प्रचार सामग्री में जगह दी जा रही है। भारद्वाज ने कहा कि यह वही सरकार है जो आदिवासी समाज को केवल वोट बैंक के रूप में देखती है और उनकी वास्तविक ज़रूरतों को लगातार नज़रअंदाज़ करती रही है।

आप नेताओं ने बताया कि गुजरात के डेडियापाड़ा से आम आदमी पार्टी के विधायक चैतार वसावा द्वारा विधानसभा में पूछे गए सवालों के जवाब में जो आधिकारिक जानकारी सामने आई है, उसने सरकार की प्राथमिकताओं की पोल खोल दी है। प्रशासन से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए अलग-अलग मदों में भारी-भरकम खर्च किया गया। केवल पंडाल निर्माण पर लगभग 7 करोड़ रुपये खर्च किए गए, डोम पर 3 करोड़ रुपये झोंक दिए गए, मंच निर्माण पर 5 करोड़ रुपये खर्च हुए, वीआईपी मेहमानों के लिए चाय-समोसे जैसी व्यवस्थाओं पर 2 करोड़ रुपये लगाए गए और लोगों को लाने-ले जाने के लिए बसों पर करीब 7 करोड़ रुपये खर्च कर दिए गए। आप नेताओं का कहना है कि ये आंकड़े किसी राजनीतिक आरोप का नहीं, बल्कि सरकारी दस्तावेज़ों का हिस्सा हैं। अनुराग ढांडा ने इन आंकड़ों की तुलना करते हुए कहा कि यही सरकार आदिवासी छात्रावासों में रहने वाले बच्चों को पूरे महीने के लिए सिर्फ 2,100 रुपये देती है, जिसमें उनका खाना, बिजली और अन्य सभी खर्च शामिल होते हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ अधिकारियों और वीआईपी लोगों के लिए एक ही दिन में हजारों रुपये का भोजन और सुविधाएं, दूसरी तरफ बच्चों के लिए पूरे महीने का खर्च भी नाकाफी—यह अंतर सरकार की सोच और संवेदनशीलता को साफ उजागर करता है। उनके अनुसार यह सिर्फ बजट का सवाल नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि सरकार किसे प्राथमिकता देती है और किसे हाशिए पर छोड़ देती है। दोनों नेताओं ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आम आदमी पार्टी आदिवासी समाज को केवल चुनावी लाभ के चश्मे से नहीं देखती। पार्टी का मानना है कि असली विकास वही है जिसमें आदिवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, समय पर छात्रवृत्ति मिले, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों और उन्हें सम्मान के साथ जीने का अवसर मिले। आप नेताओं ने कहा कि यह मुद्दा उठाकर पार्टी ने सिर्फ राजनीति नहीं की है, बल्कि उन हजारों-लाखों परिवारों की आवाज़ उठाई है जिनका भविष्य आज सरकारी फाइलों और बजट की कमी के बीच अटका हुआ है। गुजरात के डेडियापाड़ा से उठी यह आवाज़ अब राज्य की सीमाओं से बाहर निकलकर राष्ट्रीय बहस का रूप लेती जा रही है। वीआईपी कार्यक्रमों पर हुए खर्च के ये आंकड़े केवल पैसों का हिसाब नहीं हैं, बल्कि यह बताते हैं कि सरकार की नीतियों का केंद्र क्या है और किन वर्गों को लगातार नज़रअंदाज़ किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि अब जनता खुद तय कर रही है कि उसे वीआईपी चमक-दमक चाहिए या अपने बच्चों के लिए शिक्षा, पोषण और सुरक्षित भविष्य। यह सवाल केवल गुजरात का नहीं, बल्कि पूरे देश के विकास मॉडल और उसकी प्राथमिकताओं पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न बनकर खड़ा हो गया है।

2026 की चुनावी तैयारी का बड़ा कदम, चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में मतदाता सूची का महत्त्वपूर्ण पड़ाव

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत और पारदर्शी बनाने की दिशा में भारत निर्वाचन आयोग ने एक और अहम पहल की है। आयोग मंगलवार को केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित करने जा रहा है। यह प्रक्रिया 2026 में प्रस्तावित विधानसभा और अन्य चुनावों की तैयारियों का एक निर्णायक चरण मानी जा रही है, क्योंकि मतदाता सूची ही किसी भी चुनाव की बुनियाद होती है। आयोग का यह कदम न केवल चुनावी मशीनरी को समय से तैयार करने की मंशा दर्शाता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रह जाए।

निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि मसौदा मतदाता सूची को अंतिम रूप देने से पहले सभी संबंधित पक्षों को अपनी बात रखने का पूरा अवसर दिया जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत तैयार ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स को मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारियों के माध्यम से सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा किया जाएगा। राजनीतिक दलों को यह अधिकार होगा कि वे सूची का बारीकी से परीक्षण करें और यदि किसी प्रकार की त्रुटि, छूट या आपत्ति हो तो उसे निर्धारित समय सीमा के भीतर दर्ज करा सकें। आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि राजनीतिक दलों को मतदाता सूची की हार्ड कॉपी भी उपलब्ध कराई जाए, ताकि वे जमीनी स्तर पर उसका सत्यापन कर सकें और किसी भी प्रकार की अनियमितता को समय रहते सामने ला सकें।

इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। निर्वाचन आयोग ने आम नागरिकों की सुविधा और विश्वास को ध्यान में रखते हुए ड्राफ्ट मतदाता सूची को संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी की आधिकारिक वेबसाइटों पर अपलोड करने का निर्णय लिया है। इसका सीधा लाभ यह होगा कि कोई भी नागरिक घर बैठे ऑनलाइन अपनी जानकारी जांच सकता है। इसके साथ ही आयोग अनुपस्थित मतदाताओं, स्थानांतरित मतदाताओं, मृत मतदाताओं और डुप्लीकेट प्रविष्टियों से संबंधित सूचियां भी सार्वजनिक करेगा, ताकि मतदाता सूची को अधिक से अधिक शुद्ध और विश्वसनीय बनाया जा सके।

मसौदा मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद दावा और आपत्ति की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसे चुनावी व्यवस्था का सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। इस दौरान चुनावी पंजीकरण अधिकारी संबंधित दावों और आपत्तियों पर नोटिस जारी करेंगे, सुनवाई करेंगे और तथ्यों के आधार पर निर्णय लेंगे। निर्वाचन आयोग ने साफ शब्दों में कहा है कि इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी योग्य और वास्तविक मतदाता का नाम न तो गलत तरीके से हटाया जाएगा और न ही किसी को अनावश्यक रूप से बाहर रखा जाएगा। यदि किसी नागरिक का नाम गलती से सूची में शामिल नहीं हो पाया है, तो उसे इस अवधि में जोड़ने का पूरा अवसर मिलेगा।

आयोग का यह भी कहना है कि मतदाता सूची में किसी भी प्रकार का संशोधन पूरी तरह नियमों और कानूनी प्रक्रिया के तहत ही किया जाएगा। बिना उचित कारण और सुनवाई के किसी भी नाम को हटाने की अनुमति नहीं होगी। यह निर्देश इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अतीत में मतदाता सूची से नाम हटने को लेकर कई बार विवाद और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप देखने को मिले हैं। आयोग का उद्देश्य इन सभी आशंकाओं को दूर करना और जनता का भरोसा कायम रखना है।

दावा-आपत्ति की पूरी प्रक्रिया के समाप्त होने के बाद सभी सुधारों और संशोधनों को शामिल करते हुए अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी। यही अंतिम सूची आगामी चुनावों में मतदान के लिए आधार बनेगी। चुनावी विशेषज्ञों का मानना है कि समय से पहले और व्यवस्थित ढंग से मतदाता सूची का अद्यतन होना निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनावों की दिशा में एक मजबूत संकेत है।

केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान एवं निकोबार जैसे भौगोलिक और सामाजिक रूप से विविध क्षेत्रों में एक साथ मतदाता सूची का यह अभ्यास दिखाता है कि निर्वाचन आयोग देश के हर हिस्से में एक समान और मानकीकृत प्रक्रिया लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। खासकर अंडमान एवं निकोबार जैसे दूरस्थ केंद्र शासित प्रदेश में यह सुनिश्चित करना कि हर पात्र नागरिक सूची में शामिल हो, एक बड़ी प्रशासनिक चुनौती भी है, जिसे आयोग गंभीरता से ले रहा है।

सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता की ओर भारत का बड़ा कदम, अब देश में ही बनेंगी आधुनिक वाहन चिप्स

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारत के तकनीकी और औद्योगिक भविष्य की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए टाटा समूह की कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और जापान की अग्रणी सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी ROHM के बीच महत्वपूर्ण साझेदारी हुई है। इस करार के साथ ही भारत में पहली बार वाहनों में इस्तेमाल होने वाली उन्नत सेमीकंडक्टर चिप्स के निर्माण का रास्ता खुल गया है। यह समझौता न केवल भारत की सेमीकंडक्टर रणनीति को मजबूती देता है, बल्कि ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में देश को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का अहम हिस्सा बनाने की दिशा में भी बड़ा कदम माना जा रहा है।

इस साझेदारी के तहत टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ROHM मिलकर ऑटोमोटिव ग्रेड की अत्याधुनिक पावर सेमीकंडक्टर चिप्स का असेंबली और परीक्षण भारत में करेंगे। इनमें विशेष रूप से Nch 100V, 300A Si MOSFET जैसे हाई-पावर चिप्स शामिल हैं, जिनका उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों, हाइब्रिड कारों और आधुनिक ऑटोमोटिव सिस्टम्स में बड़े पैमाने पर किया जाता है। इन चिप्स की भूमिका वाहन की ऊर्जा दक्षता बढ़ाने, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम को बेहतर बनाने और इलेक्ट्रिक ड्राइवट्रेन की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने में बेहद अहम होती है। दोनों कंपनियों का लक्ष्य है कि वर्ष 2026 तक इन चिप्स का व्यावसायिक स्तर पर बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर दिया जाए।

कंपनियों की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि यह सहयोग दोनों पक्षों की तकनीकी विशेषज्ञता और मौजूदा बुनियादी ढांचे का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करेगा। ROHM की अत्याधुनिक डिजाइन और पावर सेमीकंडक्टर तकनीक तथा टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की निर्माण क्षमता और भारत में उभरता सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम मिलकर एक मजबूत और भरोसेमंद सप्लाई चेन तैयार करेंगे। इससे भारत में न केवल ऑटोमोटिव उद्योग को मजबूती मिलेगी, बल्कि देश को आयात पर निर्भरता कम करने में भी बड़ी मदद मिलेगी। यह साझेदारी ऐसे समय में हुई है, जब भारत सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता को राष्ट्रीय प्राथमिकता बना चुका है। वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टर की कमी और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच भारत सरकार घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश और नीतिगत समर्थन दे रही है। टाटा-ROHM का यह करार इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिससे भारत को एक भरोसेमंद सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित किया जा सके।

ROHM के बोर्ड सदस्य और मैनेजिंग एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉ. काजुहिदे इनो ने इस मौके पर कहा कि इस सहयोग से भारत में तैयार होने वाले ROHM उत्पादों की श्रृंखला का विस्तार होगा और एशिया क्षेत्र में एक मजबूत और स्थिर सप्लाई चेन विकसित की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि भारत में ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है और स्वदेशी सेमीकंडक्टर की मांग लगातार बढ़ रही है। यह साझेदारी उस मांग को पूरा करने के साथ-साथ तकनीकी नवाचार को भी गति देगी।

टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की भूमिका इस पूरे परिदृश्य में बेहद अहम मानी जा रही है। कंपनी गुजरात के धोलेरा में देश की पहली व्यावसायिक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट स्थापित कर रही है, जिसमें करीब 11 अरब डॉलर का निवेश किया जा रहा है। यह परियोजना भारत के सेमीकंडक्टर सपने की रीढ़ मानी जा रही है, जहां बड़े पैमाने पर चिप्स का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही असम के जगरोड में करीब 3 अरब डॉलर की लागत से देश की पहली स्वदेशी OSAT यानी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग यूनिट भी स्थापित की जा रही है। यहां चिप्स की असेंबली, पैकेजिंग और गुणवत्ता जांच का काम होगा।

इन दोनों इकाइयों के शुरू होने से ऑटोमोबाइल, मोबाइल फोन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और एयरोस्पेस जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। खास तौर पर इलेक्ट्रिक वाहनों के तेजी से बढ़ते बाजार को देखते हुए भारत में ऑटोमोटिव ग्रेड सेमीकंडक्टर का घरेलू उत्पादन रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे लागत में कमी आएगी, सप्लाई में स्थिरता बनेगी और भारतीय कंपनियां वैश्विक बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेंगी।

कुल मिलाकर, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ROHM की यह साझेदारी केवल एक कारोबारी समझौता नहीं है, बल्कि यह भारत के तकनीकी आत्मनिर्भरता के सपने की दिशा में एक ठोस कदम है। आने वाले वर्षों में जब भारत में बने सेमीकंडक्टर चिप्स भारतीय सड़कों पर दौड़ते वाहनों में इस्तेमाल होंगे, तब यह साझेदारी देश के औद्योगिक इतिहास में एक निर्णायक मोड़ के रूप में याद की जाएगी।

भारत-न्यूजीलैंड ने ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए जिससे आर्थिक साझेदारी के एक नए युग की शुरुआत हुई: फियो अध्यक्ष

(जीएनएस)। नई दिल्ली । 22 दिसंबर, 2025: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री श्री क्रिस्टोफर लक्सन के दूरदर्शी मार्गदर्शन और नेतृत्व में और माननीय केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री श्री टॉड मैकक्ले के घनिष्ठ और सहयोगात्मक जुड़ाव के माध्यम से, भारत और न्यूजीलैंड ने रिकॉर्ड नौ महीनों में एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को सफलतापूर्वक पूरा किया है। यह ऐतिहासिक उपलब्धि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस घोषणा का स्वागत करते हुए, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (फियो) के अध्यक्ष श्री एस सी रल्हन ने कहा कि इतने कम समय में भारत-न्यूजीलैंड एफटीए का पूरा होना दोनों देशों की मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और साझा आर्थिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह समझौता भारतीय निर्यातकों के लिए गेम-चेंजर साबित होगा और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ भारत के एकीकरण को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा।

लागू होने पर, भारत-न्यूजीलैंड एफटीए भारत के 100 प्रतिशत निर्यात पर शून्य-शुल्क पहुंच प्रदान करेगा, जिसमें सभी टैरिफ लाइनों पर टैरिफ समाप्त कर दिया जाएगा। यह समझौता किसानों, एमएसएमई, श्रमिकों, कारीगरों, महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों और युवाओं को भी लाभ पहुंचाएगा, जबकि कपड़ा, परिधान, चमड़ा और जूते जैसे श्रम-गहन क्षेत्रों के लिए अपार अवसर पैदा करेगा। इंजीनियरिंग और विनिर्माण, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, प्लास्टिक, फार्मास्यूटिकल्स और रसायन सहित प्रमुख क्षेत्रों को भी महत्वपूर्ण लाभ होने की उम्मीद है। श्री रल्हन ने कहा कि सभी टैरिफ लाइनों पर भारतीय निर्यात के लिए शून्य-शुल्क पहुंच एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह न्यूजीलैंड के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएगा और रोजगार सृजन करने वाले क्षेत्रों को एक बड़ा बढ़ावा देगा।

फियो प्रमुख ने दोहराया कि एफटीए द्विपक्षीय निवेश को एक मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करता है, जिसमें न्यूजीलैंड अगले 15 वर्षों में भारत में विशेष रूप से विनिर्माण, बुनियादी ढांचे, सेवाओं, नवाचार और रोजगार सृजन में 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री रल्हन ने यह भी कहा कि एफटीए के तहत निवेश प्रतिबद्धता भारत की विकास गाथा में विश्वास का एक शक्तिशाली संकेत है और विनिर्माण विस्तार, नवाचार और रोजगार सृजन में सार्थक योगदान देगी, जिससे भारत के निर्यात क्षेत्र को और बढ़ावा मिलेगा। किसानों के कल्याण पर खास ध्यान देते हुए, यह समझौता न्यूज़ीलैंड को भारतीय कृषि निर्यात के लिए नए अवसर खोलता है, जिसमें फल, सब्जियां, कॉफी, मसाले, अनाज और प्रोसेस्ड फूड शामिल हैं। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पार्टनरशिप, सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस की स्थापना, और न्यूज़ीलैंड की एडवांस्ड कृषि-तकनीकों तक पहुंच जैसी पहल से उत्पादकता, गुणवत्ता और किसानों की आय में सुधार करने में मदद मिलेगी। श्री रल्हन ने कहा कि शहद, कीवीफ्रूट और सेब जैसे बागवानी उत्पादों के लिए लक्षित समर्थन स्थायी कृषि विकास को और मजबूत करेगा।

फियो अध्यक्ष ने यह भी कहा कि यह एफटीए न केवल बाजार पहुंच का विस्तार करता है, बल्कि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और उत्पादकता बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित करता है, जो भारतीय किसानों को वैल्यू चेन में आगे बढ़ने और उच्च आय प्राप्त करने में मदद करेगा। घरेलू संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, भारत ने प्रमुख कृषि और संबंधित उत्पादों, जिसमें डेयरी, चीनी, कॉफी, मसाले, खाद्य तेल, कीमती धातु (सोना और चांदी), कीमती धातु स्क्रैप, तांबा कैथोड और रबर-आधारित उत्पाद शामिल हैं, की सुरक्षा की है, जिससे किसानों, एमएसएमई और घरेलू उद्योगों के लिए पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। यह समझौता आईटी एवं आईटीईएस, वित्त, शिक्षा, पर्यटन, निर्माण और अन्य क्षेत्रों में भारत के सेवा क्षेत्र के लिए नए अवसर खोलता है। विशेष रूप से, स्वास्थ्य, पारंपरिक चिकित्सा, छात्र गतिशीलता और अध्ययन के बाद काम पर न्यूज़ीलैंड के पहले अनुबंध भारतीय पेशेवरों और छात्रों के लिए अभूतपूर्व रास्ते बनाते हैं। बढ़ी हुई गतिशीलता प्रावधान, जिसमें वर्किंग हॉलिडे वीजा, अध्ययन के बाद काम के रास्ते और कुशल भारतीय पेशेवरों के लिए 5,000 अस्थायी रोजगार वीजा का एक समर्पित कोटा शामिल है, भारतीय प्रतिभा के लिए वैश्विक करियर के अवसरों को और सुविधाजनक बनाएगा। श्री रल्हन ने कहा कि सेवाओं, गतिशीलता, छात्र अवसरों और पारंपरिक चिकित्सा पर प्रगतिशील प्रावधान दूरदर्शी हैं और भारत के कुशल पेशेवरों और युवाओं को बहुत लाभ पहुंचाएंगे।

फियो भारत-न्यूज़ीलैंड एफटीए को पारस्परिक रूप से लाभकारी और भविष्य-उन्मुख समझौता मानता है जो आर्थिक सहयोग को गहरा करेगा, लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करेगा और विकसित भारत 2047 के भारत के दीर्घकालिक विजन का समर्थन करेगा।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के समक्ष नागरिकों की प्रस्तुतियों-शिकायतों के ऑनलाइन निवारण का दिसंबर महीने का राज्य स्तरीय ‘स्वागत’ कार्यक्रम 24 दिसंबर बुधवार को आयोजित होगा

25 दिसंबर गुरुवार को क्रिसमस के सार्वजनिक अवकाश के चलते दिसंबर-2025 का राज्य स्तरीय ‘स्वागत’ कार्यक्रम बुधवार को

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में हर महीने आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय ‘स्वागत’ ऑनलाइन जन शिकायत निवारण कार्यक्रम अंतर्गत दिसंबर-2025 का राज्य स्तरीय ‘स्वागत’ कार्यक्रम 24 दिसंबर बुधवार को आयोजित किया जाएगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से वर्ष 2003 से शुरू हुए ‘स्वागत’ ऑनलाइन जन शिकायत निवारण कर्यक्रम के अंतर्गत हर महीने के चौथे गुरुवार को राज्य स्तरीय ‘स्वागत’ कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। दिसंबर महीने के चौथे गुरुवार 25 दिसंबर को क्रिसमस के सार्वजनिक अवकाश के चलते दिसंबर-2025 का राज्य स्तरीय ‘स्वागत’ कार्यक्रम 24 दिसंबर बुधवार को आयोजित करने का निर्णय किया है। नागरिक इस राज्य स्तरीय ‘स्वागत’ कार्यक्रम के लिए अपनी प्रस्तुतियाँ 24 दिसंबर बुधवार सुबह 8 से 11 बजे के दौरान गांधीनगर में स्वर्णिम संकुल-2 स्थित मुख्यमंत्री की जन संपर्क इकाई में प्रत्यक्ष आकर दे सकेंगे। मुख्यमंत्री बुधवार दोपहर बाद इस राज्य स्तरीय ‘स्वागत’ कार्यक्रम में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहकर नागरिकों की प्रस्तुतियों-शिकायतों को सुनेंगे।

सोना वायदा में 1949 रुपये और चांदी वायदा में 5341 रुपये का ऊछाल: दोनों वायदे ऑल टाइम हाई स्तर पर पहुँचे

(जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में . करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 46552.84 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 241486.19 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का दिसंबर वायदा 33825 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 3185.98 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 39692.62 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 134899 रुपये के भाव पर खूलकर, 136199 रुपये के ऑल टाइम हाई और 134899 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 134196 रुपये के पिछले बंद के सामने 1949 रुपये या 1.45 फीसदी की मजबूती के साथ 136145 रुपये प्रति 10 ग्राम बोला गया। गोल्ड-गिनी दिसंबर वायदा 1110 रुपये या 1.03 फीसदी की तेजी के संग 108487 रुपये प्रति 8 ग्राम हुआ। गोल्ड-पेटल दिसंबर वायदा 126 रुपये या 0.94 फीसदी की तेजी के संग 13566 रुपये प्रति 1 ग्राम हुआ। सोना-मिनी जनवरी वायदा सत्र के आरंभ में 132600 रुपये के भाव पर खूलकर, 134165 रुपये के दिन के उच्च और 132600 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 1717 रुपये या 1.3 फीसदी की तेजी के संग 134144 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ। गोल्ड-टेन दिसंबर वायदा प्रति 10 ग्राम सत्र के आरंभ में 132599 रुपये के भाव पर खूलकर, 134364 रुपये के दिन के उच्च और 132599 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 132780 रुपये के पिछले बंद के सामने 1500 रुपये या 1.13 फीसदी की तेजी के संग 134280 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ।

चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा सत्र के आरंभ में 209475 रुपये के भाव पर खूलकर, 214583 रुपये के ऑल टाइम हाई और 209475 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 208439 रुपये के पिछले बंद के सामने 5341 रुपये या 2.56 फीसदी की तेजी के संग 213780 रुपये प्रति किलो हुआ। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा 5442 रुपये या 2.61 फीसदी की बढ़त के साथ

क्रूड ऑयल वायदा में 98 रुपये की तेजी : कमोडिटी वायदाओं में 46552.84 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 241486.19 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 39692.62 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 33825 पॉइंट के स्तर पर

214311 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 5524 रुपये या 2.65 फीसदी की तेजी के संग 214314 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा।

मेटल वर्ग में 3580.21 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा दिसंबर वायदा 7.45 रुपये या 0.67 फीसदी की तेजी के संग 1122.3 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि जस्ता दिसंबर वायदा 1.8 रुपये या 0.6 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 303.2 रुपये प्रति किलो पर आ गया। इसके सामने एल्यूमीनियम दिसंबर वायदा 1.3 रुपये या 0.46 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 285.2 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा दिसंबर वायदा बिना बदलाव के 181.8 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 3226.02 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल जनवरी वायदा सत्र के आरंभ में 5124 रुपये के भाव पर खूलकर, 5208 रुपये के दिन के उच्च और 5114 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 98 रुपये या 1.92 फीसदी की तेजी के संग 5203 रुपये प्रति बैरल हुआ। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी जनवरी वायदा 97 रुपये या 1.9 फीसदी की तेजी के संग 5202 रुपये प्रति बैरल के भाव पर पहुंचा। इनके अलावा नैचुरल गैस दिसंबर वायदा 362.2 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 371.1 रुपये और नीचे में 361.6 रुपये पर पहुंचकर, 356.9 रुपये के पिछले बंद के सामने 10.5 रुपये या 2.94 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 367.4 रुपये प्रति एमएमबीटीयू पर आ गया। जबकि नैचुरल गैस-मिनी दिसंबर वायदा 10.2 रुपये या 2.86 फीसदी की मजबूती के साथ 367.4 रुपये प्रति एमएमबीटीयू बोला गया। कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल दिसंबर वायदा सत्र के आरंभ में 937 रुपये के भाव पर खूलकर, 1.2 रुपये या 0.13 फीसदी गिरकर 930.1 रुपये प्रति किलो हुआ।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 20492.32 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 19200.31 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 3035.81 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 259.20 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 18.01 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 267.19 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 608.04 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 2600.69 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 16936 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 80044 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 22075 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 332239 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 36522 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 17204 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 42092 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 109323 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 22537 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 44520 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स दिसंबर वायदा 33899 पॉइंट पर खूलकर, 33899 के उच्च और 33365 के नीचले स्तर को छूकर, 601 पॉइंट बढ़कर 33825 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल जनवरी 5200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 37.2 रुपये की बढ़त के साथ 170.4 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस दिसंबर 370 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 1.6 रुपये की बढ़त के साथ 6.85 रुपये हुआ।

सोना दिसंबर 139000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 281 रुपये की बढ़त के साथ 692.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी दिसंबर 215000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1162.5 रुपये की बढ़त के साथ 2610.5 रुपये हुआ। तांबा दिसंबर 1120 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 90 पैसे के सुधार के साथ 7.84 रुपये हुआ। जस्ता दिसंबर 310 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 34 पैसे की नरमी के साथ 1.03 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल जनवरी 5100 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 52.2 रुपये की गिरावट के साथ 123.2 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस दिसंबर 360 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 6.7 रुपये की गिरावट के साथ 4.7 रुपये हुआ। सोना दिसंबर 130000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 172 रुपये की गिरावट के साथ 168 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी दिसंबर 205000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 1558 रुपये की गिरावट के साथ 745 रुपये हुआ। तांबा दिसंबर 1120 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 6.76 रुपये की गिरावट के साथ 5.08 रुपये हुआ। जस्ता दिसंबर 295 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 1.13 रुपये की गिरावट के साथ 0.18 रुपये हुआ।